लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 13 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 344

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

सफलता का कोई मंत्र नहीं, यह केवल कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास का परिणाम है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi | NIGHT 28° Low

संक्षेप

यूक्रेनी बैंक से रूस का अरबों डॉलर का विवाद: पूर्व CJI चंद्रचूड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी; क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली। रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को यूक्रेन के एक सरकारी बैंक के साथ चल रहे विवाद में अपना मध्यस्थ बनाया है। यूक्रेन का सरकारी बैंक ओशचादबैंक रूस से पैसे के नुकसान की भरपाई मांग रहा है। बैंक का कहना है कि रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण यूक्रेन के कुछ इलाकों में उसकी संपत्ति और कारोबार को नुकसान हुआ। इन इलाकों में डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिज्जिया शामिल हैं। बैंक ने इस मामले को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद का फैसला कराने के लिए तीन लोगों की एक टीम बनाई गई है। रूस ने इस तीन सदस्यीय टीम में अपने पक्ष से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चुना है। यानी वह इस मामले में रूस की ओर से नियुक्त मध्यस्थ होंगे। तीन सदस्यों वाली इस टीम की अध्यक्षता कोस्टा रिका की इ्याला जिमेनेज करेंगी। उन्हें रूस और यूक्रेन के बैंक, दोनों ने मिलकर चुना है। तीसरे सदस्य ग्रीस के स्तावरोस ब्रेकौलाकिस हैं। उन्हें यूक्रेन के ओशचादबैंक ने चुना है। ओशचादबैंक ने रूस से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस दावे की रकम सैकड़ों करोड़ डॉलर बताई जा रही है।बैंक ने जुलाई 2025 में रूस को इस विवाद की जानकारी दी थी। आरोप है कि रूस की ओर से जवाब नहीं मिलने के बाद बैंक ने यह कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा, 18 अगस्त की एजीएम से पहले बड़ा फैसला

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने 'टाटा समूह' से कॉर्पोरेट जगत को हिला देने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 अगस्त को होने वाली बेहद अहम सालाना आम बैठक से ठीक पहले उठाए गए इस कदम ने उद्योग जगत में सनसनी फैला दी है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ चल रही तनातनी और अंदरूनी कलह को इस बड़े फैसले की मुख्य वजह माना जा रहा है। इस्तीफे का ऐलान करने के बाद एन. चंद्रशेखरन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टाटा संस के बोर्ड को अपने इस फैसले से आधिकारिक तौर पर अवगत करा दिया है। चंद्रशेखरन 20 फरवरी 2027 तक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद वह दोबारा इस पद पर नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने बोर्ड से यह भी अपील की है कि कामकाज की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द उनके उत्तराधिकारी के नाम पर विचार कर फैसला लिया जाए। कंपनी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 18 अगस्त को होने वाली एजीएम में शेयरहोल्डर डायरेक्टर के रूप में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर वोटिंग होनी थी। हालांकि, उनके दोबारा चुने जाने को लेकर कंपनी के भीतर अनिश्चितता और भारी तनाव का माहौल बना हुआ था। विवादित स्थिति और संभावित विरोध का सामना करने के बजाय

अमित शाह का विपक्ष को 24 घंटे का 'चैलेंज', बोले- सरकार कुछ नहीं छुपा रही, हर सवाल का जवाब देने को तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष को संसद में चर्चा के लिए 24 घंटे का समय दिया। उन्होंने कहा कि वे उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक सदन में मौजूद रहेंगे। शाह ने कहा कि सबसे पहले, 'लापता', 'भाग गए' जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूँ; मैं अपने चैंबर में बैठता हूँ, लेकिन चूँकि विपक्ष संसद को—दोनों सदनों में से किसी में भी—काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई क्या करे?

अमित शाह ने आगे कहा कि जहाँ

तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार NEET विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। हमने कहा था कि समय तय किया जाए और विपक्ष तैयार रहे। उनकी शुरुआती माँग यही थी, और हमने उसे मान लिया। मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है। उन्हें आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंपने दें। हम आज दोपहर 3:00 बजे से कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूँगा; मैं सबकी बात सुनूँगा और हर बात का जवाब दूँगा।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूँगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार किसी भी चीज़ पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ: स्पीकर को दोपहर 2:00 बजे तक एक पत्र सौंपें, हम दोपहर 3:00 बजे चर्चा शुरू करेंगे, और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दूँगा। संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ़ एक बयान देने के लिए कहते हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है। संसद में चर्चा विस्तार से होती है।

शाह ने कहा कि मैं आज दोपहर 3:00 बजे से बहस जारी रखने के लिए तैयार हूँ—चाहे देर रात तक बैठना पड़े या कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा चलानी पड़े; अगर स्पीकर इजाज़त दें तो मैं 'प्रश्न काल' को भी स्थगित करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान मौजूद रहूँगा, हर बात के नोट्स लूँगा और हर बिंदु का जवाब दूँगा ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ़ हो सके—ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। अब विपक्ष को तय करना है कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं।

अमित शाह लेक्चर दे रहे, सदन में क्यों नहीं आए: राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री लेक्चर दे रहे हैं. छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया, छात्रों पर गोली किसने चलाई? गृह मंत्री ही कार्रवाई का आदेश देता है. पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब रहे. राहुल ने कहा कि अगर वो संसद में आते तो सदन में क्यों नहीं आए? झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि हम छात्रों के खिलाफ कोई भी हुए हिंसा की सराहना नहीं करते हैं. मैं चुप नहीं हूं खोलकर बोल रहा हूं.

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा लॉन्च पर पीएम मोदी ने सुनाया अनसुना किस्सा, युवाओं को भी दी बड़ी नसीहत

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और उनके बेमिसाल संघर्षों को हर भारतीय के लिए एक सच्ची प्रेरणा बताया है। मौका था पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा के विमोचन का, जहां पीएम मोदी ने मंच से कोविंद जी की सादगी से जुड़े कई ऐसे अनसुने किस्से साझा किए, जिन्होंने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। राष्ट्रपति भवन के कड़े प्रोटोकॉल को दरकिनार करने से लेकर अपने गांव की मिट्टी चूमने तक, पीएम ने कोविंद जी की विनम्रता को सलाम किया। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया के इस दौर में 'शॉर्टकट' के खतरों से आगाह करते हुए एक बेहद अहम और जीवन बदलने वाला मंत्र भी दिया है।

जब प्रोटोकॉल दरकिनार कर पीएम की कार तक आते थे कोविंद

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बेहद भावुक और दिलचस्प वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब भी वह प्रधानमंत्री के तौर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन जाते थे, तो कोविंद जी अक्सर सारे कड़े प्रोटोकॉल और औपचारिकताओं को पीछे छोड़ देते थे। अपनी सहजता और बड़प्पन का परिचय देते हुए वह पीएम मोदी को विदा करने के लिए खुद उनकी कार के दरवाजे तक आते थे। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने कई बार पूर्व राष्ट्रपति को ऐसा करने से रोका और मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी यह सादगी और गहरी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी।

गांव की मिट्टी को किया नमन, पद छोड़ने के बाद भी कर रहे देश की सेवा

पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद की आत्मकथा 'भारतीय गणतंत्र की विजयः मेरा जीवन, मेरा संघर्ष' का विमोचन करते हुए उनके पैतृक गांव परौंख से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रपति बनने के बाद जब कोविंद जी पहली बार अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने अपने गुरुओं (शिक्षकों) के पैर छुए और अपने गांव की मिट्टी को नमन कर वहां के लोगों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि उनके इस भावुक अंदाज ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई। पीएम मोदी ने इस बात की भी जमकर तारीफ की कि राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद छोड़ने के बाद भी रामनाथ कोविंद शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) पर बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में वह आज भी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं।

कल कुछ नहीं होगा, संसद में जारी रहेगा विरोध : खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में अपना रुख बनाए रखेगा। पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा, 'कल कुछ नहीं होगा। हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं।'

आज विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 'अमित शाह जवाब दो' के नारे लगाए। विपक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी और अन्य राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग पर खरगे ने

कहा, 'इसे भेजा जाना चाहिए।' एफसीआरए देश में व्यक्तियों, संघों और संगठनों की ओर से विदेशी योगदान लेने और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि ऐसे योगदान का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो, जिसके लिए वे मिले हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और अभी संसद में इस पर विचार चल रहा है। संशोधित एफसीआरए नियम, 2026 को 22 जून को नोटिफाई किया गया था और ये लागू हैं। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा: नितिन नवीन

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद में जारी गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को विपक्ष पर संसद की कार्यवाही जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहा हंगामा विपक्ष की 'अराजक मानसिकता' को दिखाता है। नवीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता देख रही है कि चर्चा से वास्तव में कौन भाग रहा है। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बार-बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने की कोशिश की जा रही है।

जेपीएससी पेपर लीक विवाद

आईसीयू में भी देवेंद्र नाथ महतो का अनशन जारी

रांची। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन बुधवार को 19वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा। इसी बीच, छात्रों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल के बिस्तर से ही सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनका हौसला अभी भी पूरी तरह बुलंद है।

अस्पताल में लगातार दूसरे दिन अपना इलाज करा रहे देवेंद्र नाथ महतो

ने एक भावुक और कड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। महतो ने कहा, मेरा शरीर अस्पताल के बिस्तर पर है और हालत भी गंभीर बनी हुई है। शरीर कमजोर हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही संकल्प है।

लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा ; तीर्थ यात्रियों से भरी डबल डेकर बस खाई में पलटी, 1 की मौत, 38 लोग घायल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। उचौलिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर बुधवार तड़के कांवड़ियों से भरी डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस के पलटने और लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव शुरू किया। हादसे में घायल एक श्रद्धालु की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं करीब 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय के अनुसार बस में सवार लोग 15 दिन के टूर पर निकले तीर्थ यात्री थे। जिनमें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया

क्षेत्र के लोग थे। यात्रियों का जत्था हरिद्वार से गंगाजल लेकर अयोध्या में जलाभिषेक के लिए निकला था। इसके अलावा बस में अन्य सवारियां भी थीं। उन्हें केवल कांवड़िया बताना सही नहीं है। हादसे में घायल हरिशंकर लाल यादव (50) की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गंभीर रूप से घायल लांभा देवी, सरल मेहता, सुखदेव दास, सूगी देवी, हीरालाल, सुशीला देवी, सुगाता देवी और बस चालक सलाउद्दीन को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए शाहजहांपुर रेफर किया गया है। करीब 30 अन्य घायलों का पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। इनमें लालमती, सुंगति, लालजी, लावन्ती देवी, बसंती देवी, रोकवा कुमारी, गीता देवी, धीरज कुमार, होरीलाल और मनोज समेत अन्य यात्री शामिल हैं। सभी हालत खतरे से बाहर है।

बस सवार अजय कुमार ने बताया कि बुधवार तड़के बस उचौलिया गुरुद्वारे के पास नहर के किनारे पहुंची थी। इसी दौरान चालक को अचानक झपकी आ गई। बस की रफ्तार भी अधिक थी। चालक का नियंत्रण हटते ही बस सड़क से नीचे उतर गई और खाई में जाकर पलट गई। कई यात्री सीटों और बस के हिस्सों के बीच फंस गए। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों मौके पर पहुंच कर मदद की।

'मुझे कुत्ता कहलाना मंजूर है', नसीरुद्दीन शाह को 'लोमड़ी' कहकर कंगना ने किया पलटवार, बोलीं- खाते इस देश का हैं और लड़ते पड़ोसी के लिए

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने छात्र आंदोलनों पर हिंदी सिनेमा जगत के बड़े सितारों की खामोशी पर सवाल उठाए थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि बॉलीवुड के नामचीन चेहरे भले ही इस वक्त चुप हैं, लेकिन सही वक्त आने पर ही अपनी जुबान खोलेंगे। इसी तंज का करारा जवाब देते हुए कंगना ने नसीरुद्दीन शाह की देशभक्ति और उनकी मंशा पर ही सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए नसीरुद्दीन शाह से पूछा कि वह झारखंड में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चुप क्यों हैं और वहां अपनी बात क्यों नहीं रख रहे। इसके साथ

ही कंगना ने सोशल मीडिया पर पीयूष मिश्रा के उस वीडियो को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर अपनी राय दी थी। इस दौरान कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें 'लोमड़ी' तक कह डाला।

कंगना रनौत का पलटवार

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना ने खुलकर अपनी बात रखी और लिखा कि सच तो यही है कि हर कोई किसी न किसी का वफादार होता है। कंगना ने लिखा, 'सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर (देश) की रोटी खाती हूं, उसकी रखवाली करती हूं और उसके लिए लड़ती भी हूं। लेकिन नसीर साहब खाते तो इसी देश की हैं, पर लड़ाई पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। आज के दौर में इंसानों का कुत्ता कहलाना किसी कॉम्प्लिमेंट से कम नहीं है क्योंकि क्यूटनेस और वफादारी दोनों एक साथ मिलना कितना रेयर है। मुझे कुत्ता कहलाना मंजूर है, नसीरुद्दीन की तरह लोमड़ कहलाने से।' कंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज के दौर में अगर कोई किसी को कुत्ता कहता है तो यह एक तरह से तारीफ ही है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत अब बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वह नसीरुद्दीन शाह जैसी 'लोमड़ी' बनने से कहीं बेहतर एक वफादार कुत्ता बनना पसंद करेंगी।

ज़मीर दबाने के सवाल पर नसीरुद्दीन शाह का जवाब

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लोग दूसरों की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर अपने जमीर को दबाने का काम कर रहे हैं? इस पर नसीरुद्दीन शाह ने जवाब देते हुए कहा था, 'बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है।' हालांकि उन्होंने इसके आगे जोड़ते हुए यह भी कहा, 'लेकिन सवाल यह है कि वे आखिर ऐसा कब तक करते रह सकते हैं? इस बात का फैसला तो सिर्फ आने वाला वक्त ही करेगा।' इसी बयान के सार्वजनिक होने के बाद अब कंगना और उनके बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीते दिन कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर अटैक किया था, बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राहुल से सवाल किया था कि वो चर्चा से बाग क्यों कर रहे हैं, जबकि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं।

नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड की चुप्पी पर क्या कहा था?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने नई दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। 'द वायर' को दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों पर तीखा तंज कसते हुए उनकी तुलना एक ऐसे कुत्ते से कर दी थी जिसके मुंह में हड्डी दबी होती है।

कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े फर्जी वकीलों की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े फर्जी कानून डिग्री धारकों की जांच की मांग की गई है। याचिका एक वकील राजा चौधरी ने दायर की है, जिस पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल और उनके प्रसार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। यह याचिका 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दायर की गई।

सुल्तानपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा में बवाल, बेकाबू हुए समर्थक, आधे रास्ते से लौटे संयोजक

आर्यावर्त संवाददाता

लंभुआ (सुल्तानपुर)। विधानसभा मुख्यालय पर निकली भाजपा की तिरंगा यात्रा के बाद बवाल हो गया। तय मार्ग से इतर यात्रा ले जाने पर नपं अध्यक्ष समर्थक बेकाबू हो गए। सरेराह उनकी कार रोककर जमकर नारेबाजी की। कार घेरकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल, बुधवार को भाजपा का तिरंगा यात्रा कार्यक्रम तय था। इसके लिए जमखुरी निवासी ओम प्रकाश त्रिपाठी को यात्रा संयोजक बनाया गया था। तय मार्ग के लिहाज से यात्रा स्थानीय सर्वोदय इंटर कॉलेज से निकलकर वीर अब्दुल हमीद चौक (दुर्गापुर तिराहा) तक जानी थी। यात्रा में व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय नपं अध्यक्ष अवनीश सिंह को दी गई थी। नपं अध्यक्ष की तरफ से सभी के लिए

भोजन व बैठने का प्रबंध किया गया था।

ऐन मौके पर यात्रा का तय मार्ग बदलकर उसे मुख्य चौराहे से दियरा रोड - पठखौली रोड होते हुए फिर से सर्वोदय इंटर कॉलेज ले जाया गया। इससे वीर अब्दुल हमीद चौक पर हुई व्यवस्था धरी रह गई। इससे नपं अध्यक्ष समर्थक आक्रोशित हो गए। आरोप है कि भाजपा जिला महामंत्री विजय प्रताप त्रिपाठी ने राजनैतिक हित साधते हुए यह करवा दिया। मालूम हो कि बीते नपं चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय प्रताप त्रिपाठी अध्यक्ष पद से उम्मीदवार रहे। जिन्हें निर्दल प्रत्याशी अवनीश सिंह ने पराजित कर दिया था। बाद में अवनीश सिंह लखनऊ कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए थे। नपं अध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि मैने सारी व्यवस्था कर रखी थी। पर, जिला महामंत्री ने यात्रा दूसरे मार्ग से घुमवा दिया। उधर, जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है।

आधे रास्ते से घर लौट गए यात्रा संयोजक

लंभुआ। स्थानीय तिरंगा यात्रा के लिए जमखुरी निवासी ओम प्रकाश त्रिपाठी को संयोजक बनाया गया था। यात्रा के मार्ग तय करने व एसडीएम - सीओ के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी थी। मार्ग बदलने से नाराज यात्रा संयोजक ओम प्रकाश आधे मार्ग से वापस लौट गये।

पूर्व विधायक ने साधा निशाना

लंभुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडेय ने सोशल साइट पर इस प्रकरण पर भाजपा पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके पदाधिकारी को अनुशासनहीन बताते हुए उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी की लंका लगा दी है। सोशल साइट पर कार्यकर्ताओं से घिरे जिला महामंत्री विजय प्रताप त्रिपाठी की वीडियो भी पोस्ट की गई है।

करौंदीकला ब्लॉक कर्मियों पर दबंगों का कहर

आर्यावर्त संवाददाता

करौंदीकला/सुल्तानपुर। विकास खंड करौंदीकला इन दिनों दबंगई और गुंडागर्दी का अखाड़ा बन चुका है। ब्लॉक कार्यालय के भीतर घुसकर सरकारी अधिकारियों को धमकाने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सफाई कर्मी से सरेआम रंगदारी वसूलने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस दुस्साहस से पूरे ब्लॉक मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। मामले में एडीओ (सहकारिता) और एक सफाई कर्मी ने स्थानीय थाने में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

सहायक विकास अधिकारी आलोक मिश्रा की तहरीर के मुताबिक 11 अगस्त को लगभग तीन बजे अपने कार्यालय में बैठकर सरकारी काम निपटा रहे थे। इसी दौरान भटौता तुलसी पट्टी का रहने वाला अशोक निषाद और पहाड़पुर कलां के अशोक कुमार मिश्र दबंगई दिखाते हुए उनके चैंबर में घुस कर सरकारी काम रुकवा दिया और मेज पर रखे प्लास्टिक के थैले से जबरन सरकारी अभिलेख निकालकर फाड़ डाले। जब अधिकारी ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने सीधे लहजे में कहा अगर इस ब्लॉक में काम करना है, तो 50,000 रुपये की रंगदारी देनी होगी, वरना और हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सहकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी और गाली-गलौज की गई। दबंगों का हौसला यहीं नहीं रुका। इस घटना के ठीक अगले दिन यानी 12 अगस्त को ग्राम पंचायत भटौता तुलसी पट्टी के सफाई कर्मचारी अर्जुन को निशाना बनाया गया। अर्जुन देव स्थान पर सफाई कर रहा था, तब आरोपी अशोक कुमार निषाद ने दो अज्ञात गुर्गों के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेरकर रंगदारी मांगी और मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। और दबंगों ने जबरन अपने खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ति कर्मचारी ने इस अवैध वसूली का स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंपकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सरकारी कर्मचारियों पर हुए इस सीधे हमले के बाद ब्लॉक के अन्य कर्मियों में भारी आक्रोश है। ब्लॉक कर्मी मुकदमा न लिखे जाने से नाराज हैं और धरना देने के लिए लामबंद हो रहे हैं। थानाध्यक्ष अश्वनी सिंह ने बताया कि मैं अभी हाईकोर्ट में आया हूं। घटना की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। वापस लौटकर विधि सम्मत कार्यवाही करता हूं।

ज्ञापन के 24 घंटे के भीतर ने जारी किया एनपीएस अंशदान मांग पत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के लगातार प्रयासों के आगे शिक्षा विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा है। संगठन की सक्रियता के चलते विभाग ने सकारात्मक और बेहद त्वरित कार्रवाई की है। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के महज 24 घंटे के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।

इस त्वरित और बड़ी सफलता पर ठकुराई गुट के जिला मंत्री डॉ अजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष शिव नंदन यादव, सतीश मिश्रा और अन्य शिक्षक साथियों ने सभी समाचार पत्रों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस खबर को अपने समाचार पत्र में स्थान दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला मंत्री डॉ अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक का व्यवहार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सदैव सकारात्मक रहता है। उन्होंने कहा, ज्ञापन देते समय ही जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वासन दिया था कि इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ज्ञापन के अन्य बिंदुओं पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया था। शिक्षकों का मानना है कि इस संवेदनशील और जटिल मामले पर 24 घंटे के भीतर आदेश जारी होना शिक्षकों की एकजुटता और संगठन के सही दिशा में किए गए संघर्ष का सीधा नतीजा है।

दो माह चलेगा एचआईवी/एड्स जागरूकता अभियान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिले में एचआईवी/एड्स से संबंधित सघन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने किया।

शिविर के दौरान आम जनमानस से एचआईवी तथा टीबी की जांच कराने की अपील की गई। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के निर्धारित 95-95-99 लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि एचआईवी से संक्रमित कम से कम 95 प्रतिशत लोगों को अपनी बीमारी की जानकारी होनी चाहिए। इनमें से 95 प्रतिशत लोगों का उपचार शुरू होना चाहिए और उपचार ले रहे कम से कम 99 प्रतिशत लोगों का वायरल लोड पूरी तरह नियंत्रित होना चाहिए, ताकि संक्रमण दूसरों तक न फैल सके। शिविर में 72 गर्भवती महिलाओं समेत कुल 148 लोगों की एचआईवी जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को एचआईवी से बचाव, जांच और उपचार के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह सघन जागरूकता अभियान आगामी दो माह तक चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के 15 महाविद्यालयों, 60 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और 200 ग्राम सभाओं को जागरूकता अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक करने के साथ जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, जिला क्षय रोग अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों, टीआई संस्था, आईसीटीसी, पीपीटीसीटीसी तथा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों की मौजूदगी रही। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है।

भव्यता के साथ मनाया गया पद्मश्री डॉ रंगनाथन की जयंती

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय में पद्मश्री डॉ एसआर रंगनाथन की जयंती मनाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के उपप्राचार्य डॉ शक्ति सिंह, अतिथि ज्ञानचंद्र यादव, पुस्तकालय समन्वयक डा. पवन रावत, विभागाध्यक्ष डा. विश्वदीप खरवार एवं अनुशास्ता प्रमुख डा. शुधांशु प्रताप सिंह ने अपने व्यक्तव्य में अपने संस्थान के पठन-पाठन व अनुशासन से छात्र-छात्राओं को अवगत कराते हुए डा. रंगनाथन द्वारा किए गए कार्यों से परिचय कराया। साथ ही नवागत छात्रों को शुभाशीष प्रदान किया। विभाग समन्वयक व उपपुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राजेश पाण्डेय ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि छात्रों को कक्षा में आना आवश्यक है। इस अवसर पर केन्द्रीय पुस्तकालय के सुधीर सिंह, कोमल सिंह, अंजली मिश्रा, विकास राव, धर्मराज निषाद, प्रहर्ष मिश्रा, दिनेश कुमार, तहसीन बानो, कपिल यादव, रामशब्द, प्रकाश सहित पुस्तकालय विज्ञान विभाग के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।

जनगणना पूरी, मानदेय अधर में, भुगतान की सुस्त रफ्तार से कर्मचारियों में आक्रोश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कराने के बाद भी कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान लंबित रहने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन किया, लेकिन कार्य पूर्ण होने के काफी समय बाद भी अधिकांश पात्र कर्मियों को मानदेय नहीं मिल सका है। इससे विभागीय भुगतान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लंबित भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तहसील बल्दीराय प्रभारी विपिन सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों व कर्मचारियों ने बुधवार 12 अगस्त को जनगणना चार्ज अधिकारी/तहसीलदार बल्दीराय को प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें मांग की गई कि जिन कर्मचारियों ने जनगणना संबंधी दायित्व पूरा किया है, उनका सत्यापन कराकर नियमानुसार लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण शासकीय कार्य में ड्यूटी लगने पर उन्होंने अपने नियमित कार्यों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाई। इसके बावजूद मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब होना कर्मचारियों के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता और भुगतान व्यवस्था की गति पर प्रश्न खड़ा करता है। कर्मचारियों ने मांग की कि भुगतान में देरी के वास्तविक कारणों की जांच कर जिम्मेदार स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन से अपेक्षा जताई कि मामले को प्राथमिकता देकर पात्र कर्मियों का लंबित मानदेय नियमानुसार जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान आशीष शुक्ल, रजनीश कुमार, देवेंद्र मिश्र, अशोक कुमार, पवन कुमार, शिव कुमार समेत दर्जनों शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे।

पेड़ की डाल से लटका मिला किशोरी का शव

सुल्तानपुर। घर से कुछ दूरी पर बाग में किशोरी का शव पेड़ की डाल में दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ विधिक कार्यवाही शुरू की।

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के राम नगर कोट गांव से जुड़ा है। जंहा बुधवार को गांव निवासी मोनी उर्फ प्रिया (15) पुत्री उदयराज निषाद का शव गांव के बाहर पेड़ में दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम सहित उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतका पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। जो बीते चार पांच सालों से किसी अज्ञात बीमारी से जूझ रही थी। जिसमे उसके बाल पूरी तरह झड़ गए थे। इसी अवसाद के चलते उसने आत्महत्या कर ली। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है।

तिरंगे के रंग में रंगा धनपतगंज, भारत माता के जयघोष से गूंजा पूरा क्षेत्र

युवा शक्ति ने तिरंगा यात्रा निकालकर दिया राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। धनपतगंज क्षेत्र में देशभक्ति का जज्बा उस समय चरम पर पहुंच गया जब युवाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में लहराता राष्ट्रीय ध्वज और गूंजते भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो उठा। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने सहभागिता कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष धनपतगंज योगेश सिंह एवं युवा मोर्चा जिला महामंत्री गौरव मौर्य ने किया। मुख्य अतिथि रूपेश सिंह रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि त्रिनेत्र पाण्डेय, राम अकबाल द्विवेदी, कपिल देव दूबे, समाजसेवी यमुना प्रसाद पाण्डेय, पूर्व मंडल अध्यक्ष बृजभूषण मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, महेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष सूर्य नारायन पाण्डेय, पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप तिवारी, राज शेखर सिंह, मनीष सिंह और अमरपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से धनपतगंज का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। आयोजकों ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धनपतगंज के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया।

एमसीए टॉपर का अखंड योगदान एसोसिएशन ने किया सम्मान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जिले के मेधावी राहुल मिश्रा का सम्मान अखंड योगदान एसोसिएशन ने किया।

कार्यालय पर आयोजित बैठक में संस्था के निदेशक ओम कुमार वर्मा ने राहुल मिश्रा का सम्मान किया। इस दौरान श्री वर्मा ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह मुश्किल वक्त में ही मेधावी खिलते हैं। इसी क्रम में मेधावी राहुल ने बताया कि मैंने यह उपलब्धि सभी के सहयोग से हासिल किया है, इसमें सभी का आंशिक योगदान है। बैठक का संचालन विकास राव ने किया। इस मौके पर उप निदेशक राजकुमार, दिनेश कुमार, सोनू पाण्डेय, सत्यम मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, सागर वर्मा आदि मौजूद रहे।

गौरव की मेधा ने बढ़ाया बल्दीराय का गौरव, विश्वविद्यालय में रचा स्वर्णिम इतिहास

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय की माटी में पले-बढ़े एक होनहार युवा ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ग्राम ककरहिया भवानीगढ़ निवासी गौरव सिंह पुत्र डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में आयोजित दीक्षांत समारोह में शानदार शैक्षणिक उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया।

गौरव सिंह ने विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संकाय के अंतर्गत एमएससी कृषि (एग्रोनॉमी) में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें प्रतिष्ठित कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। गौरव की यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी सफलता ने यह संदेश दिया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी दृढ़ संकल्प, निरंतर अध्ययन और कठिन परिश्रम के बल पर युवा बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। स्वर्ण पदक मिलने की खबर क्षेत्र में पहुंचते ही परिवार, शिक्षकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने गौरव की उपलब्धि को बल्दीराय क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गौरव की सफलता पर शिक्षक राम सिंह, उमेश पांडेय, राम कल्प गुप्ता, अरविंद यादव, कृष्ण कुमार यादव, राम प्रकाश सिंह सहित विश्वविद्यालय परिवार एवं क्षेत्र के तमाम शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों का कहना है कि गौरव की यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

200 मोबाइल बरामद, 45 को लौटाया गया

जौनपुर। गुम मोबाइल की तलाश में परेशान लोगों के लिए पुलिस ने बड़ी राहत दी है। साइबर क्राइम सेल और विभिन्न थानों की साइबर सेल टीम ने 200 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल जौनपुर के अलावा आजमगढ़, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़ और भदोही से बरामद किए गए। वहीं कुछ मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और राजस्थान से भी बरामद हुए। बरामद मोबाइलों में वनप्लस, वीवो, रेडमी, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, पोको, नोकिया और सैमसंग समेत कई प्रमुख कंपनियों के फोन शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह ने बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए। पुलिस ने अपील की कि मोबाइल गुम होते ही पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज कराएं।

उन्नाव में युवक को हाथ–पैर बांधकर बनाया बंधक

आर्यावर्त संवाददाता

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक पड़ोसी पर आरोप है की उसने बगल के रहने वाले एक युवक को हाथ बांधकर अपने घर में बंधक बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ति युवक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और पीड़ति युवक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना गंगाघाट थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक, गंगाघाट थाना क्षेत्र के कप्तान हाता निवासी किशोर वर्मा ने पुलिस को सूचना दी की उसके पड़ोसी आनंद तिवारी ने मेरे बेटे सुमित को घर बुलाया था। सुमित जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसकी तलाश में जुट गए। तलाशी के दौरान किशोर वर्मा ने पड़ोसी आनंद के घर पर अपने बेटे सुमित को देखा, सुमित के हाथ पैर बंधे थे और वह जमीन पर लेटा था। बेटे की ऐसी हालत देख किशोर वर्मा ने पुलिस को सूचना दी।

पिता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुमित को बंधन से मुक्त कराया। बेटे को मुक्त कराने के बाद उसे लेकर थाने पहुंचे और पड़ोसी के खिलाफ बेटे को बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।

युवक को पुलिस ने कराया बंधक मुक्त

इस मामले में सीओ विन्नी सिंह ने बताया की मंगलवार की रात को सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस टीम मौके पर पहुंचे जहां पर युवक को बंधक बनाए रखने की बात सही पाई गई। सीओ के मुताबिक पुलिस ने अपनी मौजूदगी में सुमित को बंधन मुक्त कराया।

सीबीजी उद्योग में किसानों की आय बढ़ाने और गांवों में रोजगार देने की बड़ी क्षमता : ए.के. शर्मा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 के दूसरे दिन नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़कर सुनाने के साथ हुई। सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सीबीजी उद्योग में किसानों को समृद्ध बनाने की अपार क्षमता है। इसके माध्यम से कृषि अपशिष्ट और अन्य कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा

सकती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया है। कृषि और किसानों को मजबूत बनाने के लिए स्वाइल हेल्थ कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।उन्होंने बायोएनर्जी क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि अपशिष्ट, पशुधन अवशेष और अन्य जैविक संसाधनों का पर्याप्त भंडार है, जिसका वैज्ञानिक एवं आर्थिक उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि वे केवल राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से किसानों और युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विकास और कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों को समझना चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बायोएनर्जी सम्मेलन इसका उदाहरण है, जहां देश-विदेश के उद्यमी और विशेषज्ञ किसानों की आय बढ़ाने, कृषि अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां बड़ी मात्रा में कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि अपशिष्ट को आय और ऊर्जा के स्रोत में बदलकर किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने बायोएनर्जी क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत और गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में घरेलू स्तर पर एक लाख छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि गोबर और अन्य पशुधन जैव-अवशेषों के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान केआईएस और पारस समूह के साथ एक हजार करोड़ रुपये के निवेश का समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। इसके अलावा विभिन्न शोध पत्रिकाओं और कृषि साहित्य का विमोचन किया गया।सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और उद्यमियों ने बायोएनर्जी, सीबीजी, कृषि अपशिष्ट के वैज्ञानिक उपयोग, ग्रामीण रोजगार और हरित ऊर्जा के विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कृषि एवं पशुधन आधारित जैव-अवशेषों को ऊर्जा में बदलने की तकनीक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

रक्षाबंधन पर छह दिन चलेगी अतिरिक्त बस सेवा, परिवहन निगम की सभी बसें सड़क पर उतरेंगी

लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिया है कि 26 से 31 अगस्त तक छह दिनों की अवधि में अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए, ताकि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें।परिवहन राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप रक्षाबंधन पर्व के दौरान प्रदेश में कहीं भी बहनों को आने-जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर्व से पहले और बाद में यात्रियों का आवागमन सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए परिवहन निगम की शत-प्रतिशत बसों को ऑन रोड रखने और यात्रियों की मांग के अनुसार अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत में अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार, आधार-पैन समेत भारतीय दस्तावेज बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस ने भारत में अवैध रूप से निवास कर रही उज्बेकिस्तान की करीब 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई भारतीय दस्तावेज, दो मोबाइल फोन, बैंक कार्ड, नकदी और सोने-चांदी जैसी धातुओं के आभूषण बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से मिली सूचना के आधार पर की गई।पुलिस के मुताबिक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में 20 जून 2025 को धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ कमाने के लिए ऐसे विदेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने में सहयोग करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनके पासपोर्ट अथवा वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। मामले में विदेशी महिलाओं की पहचान बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी किए बिना प्लास्टिक सर्जरी अथवा ऑपरेशन कराए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही थी।विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों और एफआरआरओ से प्राप्त सूचना के बाद सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम ने आरोपी महिला की तलाश शुरू की। पूछताछ के बाद पुलिस ने थाना परिसर स्थित महिला हेल्प डेस्क से आरोपी महिला लोला क्यूमोवा को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला मूल रूप से ताशकंद, उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और वर्तमान में लखनऊ के राजाजीपुरम तथा सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्र में अलग-अलग पते पर रह रही थी।पुलिस के अनुसार पूछताछ में महिला ने बताया कि पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह कई वर्षों से भारत के अलग-अलग राज्यों और जिलों में छिपकर रह रही थी।

30 अगस्त तक सभी गोशालाओं की मंडलवार समीक्षा पूरी कर रिपोर्ट दें, टीकाकरण 70 प्रतिशत तक पहुंचाएं: धर्मपाल सिंह

लखनऊ। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गो-संरक्षण, गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं, हरा चारा, संचारी रोगों से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान और दुग्ध समितियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुधन, गो-संरक्षण, पशु स्वास्थ्य और दुग्ध विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए कि 30 अगस्त तक प्रदेश की सभी गोशालाओं की मंडलवार समीक्षा पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं का प्रबंधन व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से होना चाहिए तथा गोवंश के लिए हरा चारा, भूसा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहें।

महानगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर युवक को किया गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना महानगर पुलिस ने घर से लापता हुई 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए उसे बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपने साथ ले जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना महानगर में नाबालिग पुत्री को पड़ोसी इश्तियाक द्वारा घर से भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 142/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अज्ञात इश्तियाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।मामला दर्ज होने के बाद थाना महानगर पुलिस टीम नाबालिग किशोरी की बरामदगी और आरोपी की

गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग किशोरी सर्वोदय नगर बांध के पास एक व्यक्ति के साथ खड़ी है और कहीं जाने की फिराक में है।सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने सर्वोदय नगर बांध के पास से नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से आरोपी इश्तियाक अहमद पुत्र फतेह मोहम्मद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 22 वर्ष है और वह मूल रूप से ग्राम सौरंगा, बेलहरा, बाराबंकी का निवासी है। वर्तमान में वह थाना महानगर क्षेत्र के रहीमनगर में किराये के मकान में रह रहा था। पुलिस ने उसे 11 अगस्त की रात करीब 8:35 बजे हिरासत में लिया।

संक्षेप

विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी, पैसे वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। थाना मोहनलालगंज पुलिस ने विवाहिता से छेड़छाड़ कर उसका अश्लील वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धन वसूली करने और पैसे देने से इनकार करने पर मारपीट तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाना मोहनलालगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र का रहने वाला जव्वाद उर्फ जावेद उसके साथ व्यवहार बनाकर उसे अपने विश्वास में लिया। इसके बाद उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देते हुए उससे लगातार पैसे की मांग कर रहा था। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 299/2026, धारा 308(5), 76, 115(2), 351(3) बीएनएस तथा धारा 67ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया।गठित पुलिस टीमों ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 11 अगस्त 2026 को आरोपी जव्वाद उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

इंदिरानगर में पंकज तिवारी हत्याकांड का खुलासा, पांच नामजद आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। थाना इंदिरानगर पुलिस ने पंकज तिवारी हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विवेचना और पूछताछ में मृतक की गला दबाकर हत्या किए जाने तथा घटना में इस्तेमाल कपड़े को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंककर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में साक्ष्य मिटाने और सामूहिक रूप से अपराध किए जाने के आधार पर धारा 238 और 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की है।पुलिस के अनुसार, बाराबंकी के थाना बदोसराय क्षेत्र के ग्राम मरकामऊ निवासी दिनेश तिवारी ने 9 अगस्त 2026 को थाना इंदिरानगर में तहरीर देकर अपने पुत्र पंकज तिवारी की हत्या किए जाने की सूचना दी थी। तहरीर के आधार पर थाना इंदिरानगर में मुकदमा अपराध संख्या 0211/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत नेहा त्रिपाठी, बृजेश कुमार त्रिपाठी, नेहा की मां, उसके भाई बद्दू उर्फ बॉबी तथा बड़े भाई समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए। इसके बाद थाना इंदिरानगर पुलिस ने कई टीमों का गठन कर नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए 11 अगस्त 2026 को सभी पांच नामजद आरोपियों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, विवेचना और पूछताछ के दौरान सामने आया कि पंकज तिवारी की गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या में इस्तेमाल किए गए कपड़े को बाद में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंक दिया गया, ताकि घटना से संबंधित साक्ष्य को नष्ट किया जा सके। पुलिस ने आरोपियों की सामूहिक संलिप्तता और साक्ष्य मिटाने के प्रयास के तथ्य सामने आने के बाद मुकदमे में धारा 238 और 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की है।पुलिस का कहना है कि घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की जा रही है।

हज 2027 के लिए राज्य हज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति, 13 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सऊदी अरब में हज-2027 के दौरान भारतीय हज यात्रियों की सुविधा और सहयोग के लिए राज्य हज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 13 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना और केंद्र अथवा राज्य सरकार का स्थायी सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक है। 13 अगस्त 2026 को आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, स्थानीय भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के साथ कंप्यूटर में दक्ष तथा हज सुविधा एप की जानकारी रखने वाला होना चाहिए। हज के अरकान की समुचित जानकारी के साथ बड़ी सभाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और यात्रियों का मार्गदर्शन करने की क्षमता भी आवश्यक होगी। पिछले वर्षों में कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया या राज्य हज समिति से प्रतिकूल रिपोर्ट वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पूर्वांचल और मध्यांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को रफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़े उद्योगों के विस्तार को लगातार गति मिल रही है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए गए हैं। इनमें पूर्वांचल और मध्यांचल की 21 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन निवेश प्रस्तावों से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ, डेयरी और संबंधित विनिर्माण उद्योगों के नए केंद्र विकसित होने की संभावना मजबूत हुई है।पूर्वांचल में 10 परियोजनाओं के माध्यम से प्रयागराज, अमेठी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी और देवरिया जैसे जिलों में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। प्रमुख निवेशकों में वरुण बेवरेजेज शामिल है, जिसकी प्रयागराज, अमेठी और गोरखपुर क्षेत्र में परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेय पदार्थ निर्माण के औद्योगिक तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स गोरखपुर में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही है।

बीबीएयू में एंटी-रैगिंग जागरूकता सप्ताह शुरू, निकाली गई जागरूकता रैली

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देशों के अनुरूप 12 से 18 अगस्त 2026 तक एंटी-रैगिंग जागरूकता सप्ताह का आयोजन शुरू किया गया। सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों, इससे संबंधित नियमों और विश्वविद्यालय की रैगिंग के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के बारे में जागरूक किया जाएगा। जागरूकता सप्ताह के पहले दिन 12 अगस्त को प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार से पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। रैली में विद्यार्थियों को रैगिंग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने और विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन तथा आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और विरोध पर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने, शादी की बात कहने पर गाली-गलौज और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को नटकुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी अन्नू यादव पुत्र श्याम सिंह यादव, निवासी कंकड़ कुआं, दुर्गापुरी कॉलोनी, सीआरपीएफ चौराहा, थाना बिजनौर, लखनऊ के खिलाफ थाना बिजनौर में मुकदमा अपराध संख्या 202/2026 धारा 376, 323, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।पीड़िता ने आरोप लगाया था

कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी और घटना के सफल अनावरण के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने 12 अगस्त 2026 को आरोपी अन्नू यादव को नटकुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2023 में पीड़िता के संपर्क में आया था और उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुलिस से माफी मांगने की बात कही।

गिरफ्तार आरोपी अन्नू यादव पुत्र श्याम सिंह यादव की उम्र करीब 25 वर्ष है और उसने दसवीं तक शिक्षा प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ थाना बिजनौर में मुकदमा अपराध संख्या 202/2026 धारा 376/323/504/506 भादवि ही अनावरित अभियोग है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देश पर, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर कपिल गौतम द्वारा गठित टीम ने की।

महिला नेतृत्व वाली दुग्ध कंपनियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दे रहीं नई दिशा, 3.25 लाख महिला दुग्ध उत्पादक संगठित

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और उन्हें 'लखपति दीदी' के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में महिला नेतृत्व वाली पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां ग्रामीण दुग्ध अर्थव्यवस्था में बदलाव की मजबूत धुरी बनकर उभरी हैं। वर्तमान में इन कंपनियों से करीब 3.25 लाख महिला दुग्ध उत्पादक संगठित रूप से जुड़ी हैं और इनके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 12.5 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है।

लखनऊ व्यापार मंडल हुआ और मजबूत! सैकड़ों व्यापारियों के जुड़ने से बढ़ी संगठन की ताकत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में व्यापारियों के प्रमुख संगठन लखनऊ व्यापार मण्डल को उस समय बड़ी मजबूती मिली, जब वरिष्ठ व्यापारी नेता अमिताभ श्रीवास्तव, दीपक चौहान, संतोष त्रिपाठी और आशीष शर्मा ने संगठन में पुनः वापसी की। भूतनाथ स्थित होटल में ट्रान्सगोमती अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित समारोह में सभी का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया।

अमिताभ श्रीवास्तव के साथ कृष्णवीर सिंह, गौतम सिंह, सूरज यादव, अक्षय जायसवाल, अनुज सिन्हा, सुशील श्रीवास्तव, रजनीश टोडरिया, अभिषेक राय, धर्मेंद्र तिवारी, सिद्धार्थ जैन, शशि प्रताप सिसोदिया, राहुल शर्मा, मनोज सिंह, शुभम पांडे, सुधीर कुमार, अभिजीत सिंह, हेमेंद्र सिंह, विशाल चौहान, मनु

शुक्ला, दीपक शुक्ला, विक्की दयालानी, निखिल विशनानी, अमन बक्शी, निखिल तोलानी, तरुण वाधवानी, दीपक अग्रवाल, गौरव बाजपेई, रोहित राठौर, शिवम पटेल, विशाल अग्निहोत्री और शिवमूरत सहित सैकड़ों व्यापारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर यू.पी.आई. लेन-देन शुल्क, जियो टैगिंग, अतिक्रमण, ई-रिक्शा संचालन और प्रशासनिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों को लेकर व्यापारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। वरिष्ठ व्यापारी नेता अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ व्यापार मण्डल हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और सभी व्यापारियों को एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना चाहिए। वहीं ट्रान्सगोमती अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने अमिताभ श्रीवास्तव की वापसी को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे व्यापारियों की लड़ाई को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने यू.पी.आई. लेन-देन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाए जाने का विरोध किया और कहा कि डिजिटल भुगतान को पूरी तरह निःशुल्क रखा जाना चाहिए।

इस दौरान लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि अमिताभ श्रीवास्तव उनके लिए छोटे भाई की तरह थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लालफीताशाही और कुछ अधिकारियों के रवैये के कारण व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने जियो टैगिंग के नाम पर कथित उत्पीड़न, अतिक्रमण और ई-रिक्शा संचालन को लेकर स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरनाथ मिश्र ने कहा कि यदि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष और आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने के बावजूद समाधान नहीं होने की स्थिति में संगठित संघर्ष जरूरी हो जाता है। वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि लखनऊ व्यापार मण्डल व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं वरिष्ठ महामंत्री उमेश शर्मा ने अमिताभ श्रीवास्तव की वापसी को संगठन के लिए नई ऊर्जा बताते हुए कहा कि उनके अनुभव और व्यापारी वर्ग में व्यापक जनाधार से संगठन को और मजबूती मिलेगी। कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी ने कहा कि व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन विभिन्न विभागों की जटिल प्रक्रियाओं, नोटिसों और प्रशासनिक समस्याओं से व्यापारी वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने जुलूस के रूप में बाजार का भ्रमण भी किया। अंत में उपस्थित व्यापारियों ने लखनऊ व्यापार मण्डल को और मजबूत बनाने तथा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अमरनाथ मिश्र, देवेंद्र गुप्ता, पवन मनोचा, उमेश शर्मा, उत्तम कपूर, जिला महामंत्री अरविंद पाठक, नितिन जैन, अभिषेक सिंह चौहान, सतनाम सिंह, मनीष वर्मा, अभिषेक गुप्ता, चिराग जाखोड़िया, ऋषि मेहरा, रिंकू यादव और विशाल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

अफसरों जिम्मेदार ठहराने से होगा समस्याओं का समाधान

देश की सरकारों के पास हर समस्या का एक लाइलाज रामबाण इलाज यह है कि किसी समस्या की गहराई के उपचार के बजाए कानून बना दिया जाए। सरकारें हर समस्या का इलाज व्यवहारिक धरातल पर नहीं बल्कि कानून में ढूंढने की आदी हो चुकी हैं। देश में हर क्षेत्र में एक के बाद एक नए कानून बनाए जा रहे हैं, किन्तु समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, या पुराने कानूनों मे संशोधन किया जा रहा, उसका सारा भार देश के आम लोगों पर ही डाला जा रहा है। इन कानूनों में कहीं लापरवाही बरतने या अनदेखी के लिए देश के आला अफसर जिम्मेदार नहीं हैं। आजादी से लेकर आज तक ऐसा कोई कानून केंद्र या किसी राज्य ने नहीं बनाया है कि यदि कोई घटना—दुर्घटना या कांड होगा तो उसके लिए सीधे अफसर भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संशोधित केंद्रीय पेपर लीक कानून में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक का नया केंद्रीय कानून बनाने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं हुईं। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जेपीएससी के चेयरमैन एल. खियांगटे ने इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र सरकार के बनाए पेपर लीक परीक्षा कानून देश में एक अगस्त से अस्तित्व मे आ चुका है। इसके बावजूद देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले थम नहीं रहे हैं।

राजस्थान में अप्रैल 2022 में एंटी पेपर लीक एक्ट लागू किया गया। गुजरात में मार्च 2023 से सख्त नकल और पेपर लीक विरोधी कानून लागू। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश/कानून लागू किया गया। झारखंड में वर्ष 2023 में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लीक कानून के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही है।

पेपर लीक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी। निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। गैंग रेप में न्यूनतम सजा 20 साल से आजीवन की गई। इतने कठोर कानून के लागू होने के बावजूद देश में बलात्कार—हत्या के मामले बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2023 में 31,982 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इससे जाहिर है कि नए कठोर कानूनों का अपराधियों को कोई भय नहीं है। ये कानून महज कागज का पुलिन्दा साबित हो रहे हैं। यही भ्रष्टाचार का भी हाल है। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद देश से भ्रष्टाचार खत्म होना तो दूर बल्कि कम तक नहीं हो सका। आए दिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करने के लिए कभी किसी अफसर को जिम्मेदार नहीं माना गया। बेशक उनके विभाग का ही कोई भ्रष्टाचारी क्यों न पकड़ा जाए। आज तक जितने भी कानून बनाए गए हैं, उसमें अफसरों की जिम्मेदारी कहीं भी तय नहीं की गई। मसलन सड़क पर गडढा होने से यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है या फिर बगैर अग्नि सुरक्षा उपायों के संचालित किसी व्यवसायिक भवन में अग्नि दुर्घटना होती है तो इसके निगरानी करने वाले अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। यही प्रमुख वजह है कि चाहे पेपर लीक हों या किसी तरह का बड़ा हादसा, कानूनों को सख्त कर दिया जाता है, किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। इसका बड़ा उदाहरण मेलों, धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भगदड़ के दौरान होने वाली मौतें हैं। ऐसा शायद ही कोई साल जाता होगा, जब ऐसे हादसे नहीं होते होंगे। ऐसे हादसों में अब तक देश भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अफसरों की ज्मिमेदारी तय नहीं की गई। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐसे आयोजनों में हादसों के लिए सीधे अफसर जिम्मेदार ठहराएं जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा और उन्हे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

भागवत की नजरों में जेन-जी आंदोलन का दृष्टिकोण

ललित गर्ग

जंतर-मंतर से उठी हाल की युवा आवाजों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। आंदोलन को लेकर समाज में दो मत हो सकते हैं, आंदोलन की शैली, नेतृत्व और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर भी बहस हो सकती है, लेकिन एक बुनियादी सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं और विशेषकर जेन-जी को लेकर दिया गया दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने साफ कहा कि नई पीढ़ी सवाल करती है, तर्कसंगत उत्तर चाहती है, उसे केवल आदेश देकर नहीं समझाया जा सकता। उनके अनुसार आज जरूरत 'डिक्टेशन' की नहीं, 'डिस्कशन' की और आदेश की नहीं, सहमति की है। भागवत ने हाल में इससे भी आगे बढ़कर कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध माध्यम है और जेन-जी के आंदोलन में उठाई गई शिकायतें जायज हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी कह देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि आंदोलन का उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि सहमति और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत और छात्रों की नाराजगी के बीच संबंध की ओर भी उन्होंने संकेत किया।

भागवत के इस दृष्टिकोण की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि यह केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है।

भागवत के इस दृष्टिकोण की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि यह केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस मूल आत्मा को स्पर्श करता है, जिसमें सत्ता जनता से शक्ति प्राप्त करती है और जनता की आवाज सुनना उसकी संवैधानिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है। विरोध को हमेशा विद्रोह मान लेना लोकतंत्र की समझ को संकुचित करना है। असहमति को राष्ट्रविरोध समझना उससे भी बड़ी भूल है। राष्ट्र सरकार से बड़ा है और लोकतंत्र सत्ता से बड़ा। जो नागरिक देश के भविष्य को लेकर सवाल करता है, वह जरूरी नहीं कि देश का विरोध कर रहा हो, कई बार वह देश को बेहतर बनाने की बेचैनी व्यक्त कर रहा होता है। आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर जब हम स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, तब हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारी आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आजादी केवल तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तक सीमित है? या इसका अर्थ यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल कर सके, व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सके और अपनी बात बिना भय के रख सके? यदि हम सचमुच विकसित भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं तो हमें भारत के युवाओं के सपनों को सुनना ही होगा। इतिहास

भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने, अपनी शक्ति पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं, वर्तमान की सक्रिय शक्ति भी हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि परिवर्तन केवल सत्ता के गलियारों से नहीं आता, वह जागरूक नागरिकों की चेतना से आता है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके लिए सपना वह नहीं था जो सोते समय दिखाई देता है, बल्कि वह था जो व्यक्ति को सोने नहीं देता। आज के युवाओं की बेचैनी को इसी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच अंतर स्वाभाविक है। पहले परिवार, विद्यालय और समाज में 'क्यों' पूछने की गुंजाइश कम थी, बड़े जो कहते थे, उसे मान लेना संस्कार समझा जाता था। आज का युवा प्रश्न करता है-क्यों, कैसे और किसलिए? वह केवल परंपरा के नाम पर किसी बात को स्वीकार नहीं करता। वह प्रमाण चाहता है, तर्क चाहता है और परिणाम देखना चाहता है। यह बदलाव चुनौती भी है और अवसर भी। यदि हम इस प्रश्नाकुलता को दबाएंगे तो कुंठा पैदा होगी, यदि इसे सही दिशा देंगे तो यही प्रश्न नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्रनिर्माण की शक्ति बनेंगे।

विचारों के टकराव से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति स्वयं 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' की संवाद परंपरा से विकसित हुई है। उपनिषदों में प्रश्न हैं, उत्तर हैं, पुनः प्रश्न हैं। भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि हमें सिखाती है कि सत्य को एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। एक ही विषय के अनेक पक्ष हो सकते हैं। इसलिए बहस लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी बौद्धिक ताकत है। समस्या बहस में नहीं, बहस के हिंसक हो जाने में है, समस्या असहमति में नहीं, असहमति के नाम पर अराजकता में है। इसीलिए भागवत की बात का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है-विरोध संविधान की मर्यादा में हो, शांतिपूर्ण हो और उसका लक्ष्य व्यक्ति को अपमानित करना नहीं, व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो। आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक अनुशासन के साथ। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है, हिंसा लोकतंत्र नहीं। प्रश्न करना स्वतंत्रता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वतंत्रता नहीं। इसलिए सरकार और आंदोलनकारी-दोनों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक बड़ी है, क्योंकि उसके पास सत्ता, प्रशासन और संस्थागत शक्ति होती है। किसी छात्र की आवाज को लाठी से दबाया जा सकता है, लेकिन उसकी आशंका को लाठी से समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी आंदोलनकारी को राष्ट्रविरोधी कह देने से उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। यदि उसकी मांग गलत है तो तथ्य और तर्क से उसे गलत सिद्ध किया जाए। यदि मांग सही है तो उसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? लोकतंत्र में सरकार का सबसे प्रभावी हथियार पुलिस नहीं, संवाद है। यहां मोहन भागवत की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह दिखाई देती है। उन्होंने अनेक अवसरों पर केवल प्रशंसा करने के बजाय व्यापक सामाजिक हित के प्रश्न उठाए हैं। जब सत्ता या व्यवस्था किसी दिशा में आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ती दिखाई देती है, तब एक जिम्मेदार मार्गदर्शक का दायित्व होता है कि वह उसे आत्ममंथन की ओर ले जाए। भागवत की यह भूमिका हमें महाभारत के भीष्म पितामह की याद दिलाती है-ऐसे व्यक्ति की, जो सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी समय-समय पर धर्म, मर्यादा और व्यापक हित की याद दिलाता है। यह तुलना व्यक्ति-पूजा के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका की व्याख्या के लिए है। सरकारें जब जनता की आवाज समय पर सुनती हैं तो आंदोलन समस्या बनने से पहले समाधान बन सकता है। लेकिन जब शिकायतें महीनों और वर्षों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं, जब संवाद के रास्ते बंद होते जाते हैं और जब नागरिक को लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, तब असंतोष सड़क पर आता है। फिर वही आंदोलन राजनीतिक दलों, अवसरवादी तत्वों और निहित स्वार्थों के लिए मैदान बन जाता है। परिणामतः मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और आंदोलन का चरित्र बदलने लगता है। यही वह स्थिति है जिससे लोकतंत्र को बचाना है। नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने भी यही संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार और संस्थाओं को असाधारण संवेदनशीलता दिखानी होगी। परीक्षा केवल एक प्रश्नपत्र नहीं होती, वह लाखों परिवारों के वर्षों के परिश्रम, सपनों और आर्थिक-सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी होती है। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी मेहनत निष्पक्ष व्यवस्था में नहीं आंकी गई, तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है।

व्यंग्य

मंजूरियां वैध बनी रहेंगी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यावहारिक अर्थ है कि बिना पर्यावरण मंजूरी लिए शुरू की गईं परियोजनाओं को बाद में हरी झंडी देने का आम रास्ता बंद किया गया है, लेकिन अनेक गलियां खुली रखी गई हैं।

बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के शुरू कर दी परियोजनाओं को बाद में हरी झंडी देने के लिए 2021 में जारी ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपर से केंद्र और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भले बड़ा झटका मालूम पड़े, लेकिन असल में न्यायालय ने बीच का रास्ता निकाला है। इससे सिर्फ यह होगा कि ऐसी परियोजनाओं को सामान्य आदेश के तहत पोस्ट फैक्टो मंजूरी नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्र हर परियोजना को अलग आदेश के जरिए मंजूरी दे सकेगा। केंद्र ने 2021 में 2017 की अधिसूचना को निष्प्रभावी बनाने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। 2017 की अधिसूचना के तहत पोस्ट फैक्टो (परियोजना शुरू होने के बाद) मंजूरी पर रोक लगी हुई थी।

अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए भविष्य में पोस्ट फैक्टो मंजूरियां नहीं दी जा सकेंगी, लेकिन अब तक दी जा चुकीं मंजूरियां वैध बनी रहेंगी। इस तरह लगभग 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पर्यावरण संरक्षण संबंधी शर्तों से मुक्त कर दिया है। भविष्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे तो वैधानिक अधिसूचना या माफी (एमनेस्टी) योजना के जरिए असाधारण मामलों में पोस्ट-फैक्टो मंजूरी दे सकेगी। कोर्ट कहा है कि असाधारण या सार्वजनिक हित में पोस्ट फैक्टो मंजूरी देना हो, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा 3 के तहत विधिवत अधिसूचना/ संशोधन जारी करना अनिवार्य होगा।

यानी इस माध्यम से मंजूरी का रास्ता खुला रखा गया है। तीन जजों की बेंच ने यह व्यवस्था भी दी कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष परिस्थितियों में पोस्ट-फैक्टो मंजूरी देने का असाधारण अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो इस फैसले का व्यावहारिक अर्थ है कि बिना पर्यावरण मंजूरी लिए शुरू कर दी गई परियोजनाओं को बाद में हरी झंडी देने का आम रास्ता बंद किया गया है, लेकिन अनेक गलियां या पगडंडियां खुली रखी गई हैं। 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को पर्यावरण संरक्षण पर कॉरपोरेट हितों को तहजीह देने के सरकारी नजरिए का उदाहरण माना गया था। इस नजरिए को आगे बढ़ने के लिए केंद्र के पास आगे भी पर्याप्त अवसर बने रहेंगे।

ब्लॉग

छत्तीसगढ़ का लोक-पर्व हरेली तिहार

धनंजय राठौर

छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लोक-त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें प्रकृति, कृषि और जीव-जंतुओं के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। इन्हीं त्योहारों में सबसे पहला और प्रमुख त्यौहार है — हरेली तिहार। सावन माह की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) को मनाया जाने वाला यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन, कृषि परंपरा और पर्यावरण-प्रेम का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उसकी प्रकृति नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएँ भी हैं।

छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में पर्व और त्यौहारों की बहुलता है। प्रत्येक माह कोई न कोई त्यौहार यहाँ लोक मानस को अपने रंग में रंग लेता है। ये त्यौहार जहाँ लोक जीवन में हंसी-खुशी के अवसर उपलब्ध कराती हैं, वहीं खेल और मनोरंजन के अनुकूल साबित होते हैं। प्रकति का यह हरापन छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में भी पूरी समाहित है। हरेली, भोजली, जँवारा हो या बसंत पंचमी सभी पर्वों में प्रकृति का मनोरम और इसका अप्रतिम सौंदर्य झलकता है। इस रूप-सौंदर्य में जीवन की चारों अवस्थाओं का उल्लास और उत्साह विविध रंगों में बिखरा हुआ है।

शायद 'हरेली का हरापन हमारी परंपराओं में हमारे संस्कारों में और हमारे लोक जीवन में प्राकृतिक हरीतिमा का ज्यादा एहसास कराता है। हरेली का यह हरापन सबके जीवन में बिखरे और निखरे यही कामना है। यह भी कामना है कि भौतिकता की चकाचौंध से परे हमारी खेल परंपराएँ जीवित रहे ताकि माटी से जुड़े ग्रामीणजन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ रहें। माटी की सोंधी-सोंधी महक हमारे लोक गीतो से आती रहे और खेल परंपरा की यह अविरल धारा निरंतर गतिमान रहे। हरेली शब्द हरियाली से बना है। सावन के महीने में जब चारों तरफ़ खेतों और मैदानों में हरी-भरी फसलें और हरियाली लहलहाने लगती है, तब किसान इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का पहला तिहार माना जाता है, जहाँ से राज्य के प्रमुख लोक-पर्वों की श्रृंखला शुरू होती है।

हरेली का दिन मुख्य रूप से कृषकों और कृषि से जुड़े साधनों का धन्यवाद ज्ञापित करने का दिन है:

कृषि यंत्रों की पूजाः- हरेली की जड़ें छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कृषि विरासत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह एक उत्सव होने के साथ-साथ एक आध्यात्मिक भेंट भी है, लोगों के लिए प्रकृति, बारिश और अपने कृषि कार्य को सम्पन्न करने के बाद किसान अपने औजार, हल, फावड़ा, कुदाल, कुदाली, कुम्हड़ी, बिन्धना, बसुला, हथौड़ी, आरी,असिया, पैसुल, छूरा, खुर्पी आदि को धोकर स्वच्छ मिट्टी (मुरमी) का आसन से सजाकर किसान-किसानिन पूजा सामग्री रखकर धुले हुए चांवल आटे से हाथा लगाकर चन्दन, फूल, धुप-दीप व चीला रोटी से भोग लगाकर श्रीफल अर्पित करते हैं एवं भाव विभोर हो प्रार्थना करते हैं - 'हे बलराम रूपी हल प्रचण्ड शक्ति के प्रतीक धारापति, आपने कंधा के रूप में माता को संवारा एवं सेवा करने में हमारी सहायता की कृषि कार्य बोनी ब्यासी रोपा के होते ही चहूओर हरियाली छाई इसके लिए कोटिशः धन्यवाद आपका कार्य सम्पन्न हुआ विश्राम करे। हमने आपको बड़ा कष्ट दिया, काम लिया, हमें क्षमा करें। आपकी दया हम पर सदैव बनी रहे, इसी प्रकार अन्य औजारों का कार्यानुसार निवेदन करते गेड़ी की पूजा कर शरीर के सामर्थ पैरो की रक्षा की कामना करते हैं।

पशुधन का सत्कारः पशुधन किसानों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें फसल और पशुधन का संयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कम पढ़े-लिखे और अकुशल होने के कारण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। बैल छत्तीसगढ़ कृषि की रीढ़ हैं। किसान, विशेषकर सीमांत और लघु किसान, जुताई, ढुलाई और उत्पादन और इनपुट दोनों के परिवहन के लिए बैलों पर निर्भर रहते हैं।

खेती-किसानी के सच्चे साथी यानी गाय और बैलों की विशेष सेवा की जाती है। उन्हें नहला-धुलाकर आरती उतारी जाती है तथा गहूंता (आटा, नमक और जड़ी-बूटी से बना पौष्टिक मिश्रण) खिलाया जाता है, ताकि वे रोगों से मुक्त रहें। जड़ी बुटियों से तैयार औषधि को गौठान में ले जाकर अन्डी एवं खम्हार के पत्तों में नमक, चावल या गेहूँ के गोला के साथ दवा डाल कर पशुओं को खिलाया जाता है। अरण्ड, खम्हार का पत्ता औषधि है, जो वायुजनित रोगों को दूर करता है। नमक उत्प्रेक्षण का कार्य करता है, चावल या गेहूँ के कारण दवा अधिक असरकारक बन जाती है। इससे पशु धन निरोग हो जाता है यह एक प्रकार टीकाकरण ही है।

गेड़ी चढ़ने का आनंदः- इस पर्व में गेंड़ी का काफी महत्व है बांस के मोटे डंडो एवं बांस के पहुये को विशेष विधि से कस कर बांधा जाता है। गेड़ी का उदारण हमें पुराणों में मिलता है। बलदाऊ-कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेड़ी चढ़ा करते थे। कृष्ण लीला प्रसंग में इसका उदाहरण मिलता है तथा खेलों का आयोजन भी होते रहे हैं, जिसमें गेड़ी दौड़, पानी पिलाना, एक पैर में खड़े होना, एक पैर में कूदना आदि अनेक खेल का आयोजन प्राचीन काल से अब तक होते आ रहे हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर चलने के साधन के रूप में शुरू हुई यह परंपरा आज एक मनोरंजक खेल बन चुकी है।

विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजनः-हरेली में गाँव व शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होती है। सुबह पूजा-अर्चना के बाद गाँव के चौक-चौराहों पर युवाओं की टोली जुटती है और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन की जाती है। नारियल हारने और जीतने का यह सिलसिला देर रात तक चलता है। गाँव-गाँव में गेड़ी दौड़ का आयोजन होता है। कहीं खो-खो तो कहीं फुगड़ी, कहीं बिल्लस, कहीं अत्ती-पत्ती, डंडा पचरंगा खेल का आयोजन होते आ रहे हैं। गाँव का गौठान हो या स्कूल का मैदान, गाँव के बाहर सड़क हो या चौबट्टा लगता है सारे लोग रंग-बिरंगे परिधानों में सजे रहते हैं।

टोटका और सुरक्षा का विधानः- मान्यतानुसार, इस दिन गाँव को बुरी नज़र और रोगों से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजों पर नीम की पत्तियाँ बांधी जाती हैं। लोहार द्वारा घरों के चौखट पर नीम की शाखाएं और लोहे की कीलें लगाई जाती हैं। स्थानीय मान्यता है कि इससे घर को बुरी शक्तियों और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यह प्रथा नीम के ज्ञात औषधीय गुणों और ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक मान्यताओं में इसकी भूमिका से प्रेरित है।

हरेली तिहार में बनाए जाने वाले ब्यंजनः- मुख्य रूप से गुड़ के चीला, अईरसा, चौसेला और बोबरा जैसे पारंपरिक पकवान बनाए और बांटे जाते हैं। गुलगुला भजिया, गुड़हा चीला, सोहारी, बड़ा, ठेठरी, खुरमी और बोबरा जैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों का भोग कृषि औजारों और गोधन को लगाया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विशेष आनंद लिया जाता है।

हरेली तिहार केवल एक धार्मिक या लोक-अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव का प्रकृति के साथ अटूट संबंध दर्शाता है। यह पर्व सिखाता है कि जो प्रकृति और पशुधन हमें जीवन और भोजन देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है।आज के समय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर और छत्तीसगढ़िया क्रांति के तहत पारंपरिक खेलों (जैसे गेड़ी दौड़) को बढ़ावा देकर इस लोक-सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

लेखक संयुक्त संचालक, जनसंपर्क हैं

नेपाल में 'संदीप' बनकर छिपा था फरजान, 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी नेटवर्क में गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास कराने वाले सिंडिकेट के पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरजान हाशमी के रूप में हुई है। फरजान बरेली के चर्चित हाशमी सुरमा कारोबार से जुड़े परिवार का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, GST विभाग की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरजान नेपाल भाग गया था। वहां वह अपनी पहचान छिपाकर संदीप नाम से रह रहा था।

पुलिस की जांच में इस पूरे नेटवर्क में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बैंक लेनदेन सामने आया है। वहीं, पूछताछ में 80 करोड़ रुपये से अधिक की रकम अलग-अलग खातों से निकालकर बांटने और लाभार्थी

फर्मों तक पहुंचाने की जानकारी मिलने की बात पुलिस ने कही है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही फर्जीवाड़े की वास्तविक रकम और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की तस्वीर साफ होगी।

पुलिस के अनुसार, गिरोह ने कई ऐसी फर्में तैयार की थीं, जिनका जमीन पर कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। फर्जी दस्तावेजों और क्रेडेंशियल्स के जरिए इन फर्मों का GST रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। इसके बाद बिना किसी सामान की वास्तविक खरीद-बिक्री के करोड़ों रुपये के बिल काटे जाते थे। इन फर्जी बिलों के आधार पर दूसरी फर्में ITC का दावा करती थीं। इसके बाद बैंक खातों में रकम का लेनदेन किया जाता और कई खातों के जरिए पैसा घुमाकर नकद निकासी करने का आरोप है। जांच में FS Traders, सिद्धि विनायक एंटरप्राइज, मां एंटरप्राइज, नाईट स्टार , आर्ट लाइफ़ एसोसिएट, अर्हम एग्रो फूड्स और के एच इंटरप्राइजेज समेत कई फर्मों के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इन फर्मों के बीच फर्जी बिलिंग की पूरी चेन तैयार की गई थी।

DM कंपाउंड के सामने चल रहा था ऑफिस

पूछताछ में फरजान ने पुलिस को बताया कि बरेली में DM कंपाउंड के सामने एक बिल्डिंग में ऑफिस खोला गया था। यहां वह विनीत अरोरा और अनुज अग्रवाल के साथ बैठता था। आरोप है कि इसी ऑफिस से फर्जी इनवॉइस तैयार किए जाते और फर्मों से जुड़े काम किए जाते थे। पुलिस के मुताबिक, अरहम एग्रो फूड्स समेत कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के तौर पर किया गया। लाभार्थी फर्मों से रकम इन खातों में भेजी जाती थी और फिर उसे अलग-अलग माध्यमों से निकालकर गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाया जाता था।

कौन है मास्टरमाइंड?

एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर के मुताबिक, पूछताछ में सागर अग्रवाल की भूमिका पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना के तौर पर सामने आई है। आरोप है कि वह फर्जी फर्मों और लाभार्थी फर्मों के बीच मुख्य कड़ी का काम करता था। विनीत अरोरा, अनुज अग्रवाल और शिवम गुप्ता उर्फ लाला की भूमिका भी जांच में सामने आई है। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग आरोपियों को रकम के सेटलमेंट, फर्जी फर्मों के रिटर्न और पैसों को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फरजान के मुताबिक, कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद वह नेपाल चला गया था। वहां उसने अपनी पहचान छिपाकर संदीप नाम से रहना शुरू किया और कपड़ों आदि की फेरी लगाकर खर्च चलाने की बात कही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि नेपाल में रहने के दौरान वह गिरोह के संपर्क में किस तरह रहा।

पुलिस ने बरामद किए कई उपकरण

पुलिस ने फरजान के पास से एक लैपटॉप, चार्जर, माउस और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन उपकरणों से मिले डेटा, चैट और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस मामले में पहले सद्दाम हुसैन और मोहम्मद समद उर्फ शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरजान समेत अब तक पांच आरोपियों को जेल भेजे जाने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस की नजर अब सागर अग्रवाल समेत फरार आरोपियों और इस नेटवर्क से जुड़ी लाभार्थी फर्मों पर है।

50 लाख की साइबर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर। पेट्रोल पंप मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को सस्ते दाम पर सोलर प्लांट लगवाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चार सिम कार्ड और दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक करीब 50 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी कर चुका है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन शर्मा पुत्र राजनारायण, निवासी आमी सराय सैफ खां, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। आरोपी पेट्रोल पंप मालिकों और अन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटाकर उन्हें फोन करता था। इसके बाद सस्ते दाम पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव देकर व्हाट्सऐप पर लूमिनस कंपनी के नाम से फर्जी इस्टीमेट भेजता था।आरोपी कुल लागत की करीब आधी रकम पहले जमा कराने के नाम पर पीड़ितों से अलग-अलग किस्तों में रुपये अपने बताए खातों में मंगवाता था।

शहीद जिलाजीत सैदव अमर रहेंगे : विधायक

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। देश की सीमाओं व दुश्मनों से रक्षा करने वाले मरकर भी जिंदा रहते है। यह बातें बुधवार को सिरकोनी विकास खण्ड के इजरी गांव के शहीद जिलाजीत के शहादत दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए विधायक जगदीश राय ने कही। श्री राय ने कहा कि सैनिक अपने जान की परवाह किये बगैर भारत माता की रक्षा के लिए 24 घण्टे तैयार रहते है।उनके बदौलत ही आज देश व देश के नागरिक सुरक्षित हैं।हमें उन शहीदों के बलिदान को याद करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा।यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।कार्यक्रम के दौरान शहीद की माँ उर्मिला, छह वर्षीय पुत्र जीवांश व पत्नी पूनम ने जब शहीद को पुष्प अर्पित किया तब सभी आंखे नम हो गयी।कार्यक्रम में सपा के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य,पूर्व विधायक लालबहादुर यादव,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव,डॉ इंद्र सिंह,नंदलाल यादव,अशोक यादव आदि ने भी सम्बोधित किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ बृजेश यदुवंशी ने किया।इसके पूर्व सभी अतिथियों ने शहीद जिलाजीत यादव की मूर्ति पर हार-फूल चढ़ाकर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया।कार्यक्रम की शुरुआत में भूतपूर्व सैनिकों दिनेश यादव फौजी व के के सिंह के नेतृत्व में जिलाजीत यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।जिलाजीत यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सरस्वती निकेतन इंटर कालेज के बच्चों ने एक रैली निकाली।रैली में जिलाजीत अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा।कार्यक्रम का संचालन डॉ0 बृजेश यदुवंशी ने किया। दिनेश यादव, उमाशंकर पाठक, अजय सिंह,विनय कुमार, फिरतु यादव, बेचन यादव,आदि मौजूद रहे।

बरेली में भीषण सड़क हादसा, कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 23 घायल... टेंपो सवार की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला-रामनगर मार्ग पर मंगलवार रात रसूलपुर मोड़ के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और टेंपो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कांवड़ियों से भरी ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 23 कांवड़िया घायल हो गए। वहीं टेंपो चालक भी घायल हुआ, जबकि टेंपो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया है।

दरअसल, बरेली के रामनगर क्षेत्र के गांव किटोना से तीन अगस्त को कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से जल लेने के लिए रवाना हुआ था। हरिद्वार से लौटने के बाद कांवड़ियों ने गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद सभी कांवड़िया ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस अपने गांव किटोना लौट रहे थे। इसी

दौरान रसूलपुर मोड़ के पास सामने से आ रहे टेंपो से ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर हो गई।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ट्रॉली में बैठे अजय (15), मुनीष वर्मा (10), दिव्यांश (15), स्वाति (12), नवल (12), अनूप (17), लॉन्ग श्री (35), वीरेश (18), नन्ही (50), नितिन (14), गौरव (8), यादराम (20), शारिक (12), टिंकू (18), अखिलेश (15), राजेश्वरी (40), रिषिपाल (30), छोटी (10), अनिल (15), जयप्रकाश (15), रुपेश (15), राजकुमार (20) और तुलसी (15) घायल हो गए।

सूचना मिलते ही आंवला और रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं टेंपो चालक रवि निवासी खनगांव श्याम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति टेंपो में बैठकर कहीं जा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक कांवड़ियों के जत्थे में शामिल नहीं था। उसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर उसकी पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय, इंस्पेक्टर आंवला बीनू सिंह और रामनगर चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे की जानकारी जुटाई। वहीं, सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक कांवड़िया नहीं था, वह टेंपो में बैठकर कहीं जा रहा था। पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

संक्षेप

करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

जौनपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के ईसापुर मोहल्ले में बुधवार को करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका अपने पीछे तीन छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई है।नगर के ईसापुर निवासी 27 वर्षीया प्रिया सोनी पत्नी अजय सोनी घर में पंखे की तार लगाते समय अचानक करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन आनन-फानन में उन्हें ई-रिक्शा से जिला अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मृतका के तीन छोटे बच्चे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

श्रीअन्न पुनरोद्धार योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की श्रीअन्न (मिलेट्स) पुनरोद्धार योजना के तहत बुधवार को विकास खंड सिकरारा स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र में ब्लॉक स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए श्रीअन्न का महत्व लगातार बढ़ रहा है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा और कुटकी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और अन्य आवश्यक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।इनके नियमित सेवन से मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और जीवनशैली संबंधी अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। प्रशिक्षण के दौरान विषय वस्तु विशेषज्ञ अशोक कुमार पाल ने श्रीअन्न की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से भारतीय भोजन का हिस्सा रहे मिलेट्स आज फिर से स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं।

षादी का झांसा देने का अरोपी गिरफ्तार

जौनपुर। लाइनबाजार थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में वांछित चल रहे युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लाइनबाजार थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज था और उसकी तलाश की जा रही थी।पुलिस के अनुसार अपराध निरीक्षक विजय शंकर यादव ने पुलिस टीम के साथ आरोपी मनीष गौतम पुत्र स्व. अशर्फीलाल, निवासी कलीचाबाद, थाना लाइनबाजार को गिरफ्तार किया।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

भोजन के बाद चार लोगों की हालत गंभीर

जौनपुर। बुधवार सुबह अचानक से एक ही परिवार के चार लोगों की भोजन करने के बाद हालत खराब हो गई। चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया यहां से सभी को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि पड़ोसी जनपद आजमगढ़ मेहनगर थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी 45 वर्षीय शिवकुमार गौतम , 55 वर्षीय हीरालाल 52 वर्षीया सावित्री देवी पत्नी कैसेचंद, 46 वर्षीया गीता पत्नी शिवकुमार भोजन में सुबह दाल चावल सब्जी रोटी खाने के बाद सभी लोग अपने-अपने कार्य हेतु जाने की तैयारी कर रहे थे और दो लोग घर से निकल भी गए थे। इसी दौरान लगभग भोजन के दो घंटे बाद सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ना शुरू हो गयी जिसके चलते काफी कमजोरी के साथ सभी अचेत हो गए। घटना की जानकारी होने पर गांव में अफरा तफरी मच गई और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तभी नजदीकी हॉस्पिटल सभी को ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल जौनपुर भेज दिया । यहां पर भी प्राथमिक उपचार के पश्चात सभी की हालत में सुधार न होने के कारण वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन वाराणसी न ले जाकर शहर के किसी निजी अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया कर उपचार करा रहे हैं। इसी तरह से परिवार में एक सप्ताह पूर्व अच्छे लाल, मंत्री देवी, अंतिमा को भोजन के बाद उल्टी दस्त शुरू हो गयी थी।लेकिन उपचार के बाद भी ममता की मौत हो गई थी। दूसरी बार हुई घटना के चलते आजमगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी के घर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर इस तरह की घटना बार-बार क्यों हो

सूखी पड़ी है शारदा खंड सहायक नहर

जौनपुर। केराकत तहसील क्षेत्र में शारदा खंड सहायक नहर की बदहाली और पानी की कमी के कारण धान की फसल सूख रही है। नहर में पानी न आने और लंबे समय से सफाई न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंचाई के लिए पूरी तरह नहर पर निर्भर किसान पानी के इंतजार में परेशान हैं। पानी के अभाव में धान की फसल प्रभावित हो रही है और खेतों में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। कई किसान तो पर्याप्त पानी न मिलने के कारण धान की रोपाई तक नहीं कर पाए हैं। जिन किसानों ने किसी तरह धान की रोपाई कर दी है, उनकी फसल भी पानी के अभाव में सूखने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से शारदा खंड सहायक नहर की तत्काल सफाई कराकर उसमें पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग की है।

हाथ में तिरंगा और आंखों में आंसू लिए जेन-अल्फा की रही एक ही मांग, हम भी कुछ बनना चाहते हैं

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। आजादी के बाद से पक्की सड़क को लेकर परेशान ग्रामीणों संग आए बच्चों (Gen Alpha Protest) के हाथों में तिरंगा और आंखों में आंसू थे। बच्चे यही कह रहे थे साहब हम भी पढ़कर लिखकर कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन गांव की बदहाल सड़क हमारी पढ़ाई और स्कूल की डगर में बाधक बनी हुई है। बरसात में हमारा स्कूल जाना बंद हो जाता है।

कीचड़ में गंदे होकर स्कूल जाते हैं तो वहां भी हमें भगा दिया जाता है तो भला हम कैसे पढ़े और आगे बढ़ें। यह बताते हुए कुछ छात्राएं फफक कर रो पड़ीं। अधिकारियों ने बच्चों को आश्वस्त किया कि उनकी पढ़ाई में बदहाल सड़क बाधक नहीं बनेगी। हर हाल में मार्ग का निर्माण कराकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ताकि उनका भविष्य संवर सकें।

विकासखंड कुरारा के चंदूपुर गांव समेत गंगवा का डेरा, भिखुआ डेरा, ब्रह्मा का डेरा, बचुआ का डेरा, बच्ची का डेरा, चुनकू का डेरा और बनवासी का डेरा के सैकड़ों लोग व कक्षा एक से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे अपने अभिभावकों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। यह बच्चे अपने भविष्य की दुहाई देते हुए बार बार मौके पर मौजूद अधिकारियों से बदहाल सड़क को पक्की करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव व डेरा में स्कूल न होने के कारण बच्चों को हमीरपुर जाना पड़ता है। करीब एक हजार बच्चा रोजाना जिला मुख्यालय पढ़ाई के लिए जा रहा है। लेकिन बरसात में दलदल वाली सड़क इनकी पढ़ाई में बाधक बन जाती है।

हर वर्ष की यह समस्या उनके सामने बनी रहती है और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दलदल से होकर गुजरने वाले छात्र छात्राओं के कीचड़ लगने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। इतना ही नहीं कई बार बच्चे दलदल में गिरकर घायल भी हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को जब एसडीएम सदर अभिषेक कुमार व सीओ यशपाल सिंह के समझाने पर छात्राएं बोलीं कि साहब हम भी आपकी तरह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन क्या करें यह बदहाल सड़क हमारी पढ़ाई में रोड़ा बनी हुई है। जिस पर एसडीएम ने बच्चों को भरोसा देते हुए समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।

छात्राओं की बात

कई वर्षों से हमारे गांव की सड़क बदहाल पड़ी हुई है। आज तक नहीं बनी, सड़क न होने के कारण स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है।
- कंचन।

बरसात में स्कूल आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ताकि गांव की सड़क बन जाए और हम भी पढ़कर लिखकर कुछ बन जाएं।
- रजनी।

सड़कों और सम्पर्क मार्गो को गड्ढामुक्त करायें: डीएम

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन सड़कों एवं संपर्क मार्गों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें गड्ढामुक्त कराया जाए। शहरी क्षेत्र की सड़कों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल मरम्मत कराने तथा जिले की सीमा में आने वाले सभी प्रमुख और संपर्क मार्गों को एक माह के भीतर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने कहा कि टीम मौके पर जाकर सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करेगी और जियो-टैग फोटोग्राफ के साथ जांच रिपोर्ट उसी दिन शाम तक जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएगी।

कौन हैं वो पूर्व आईएएस-आईपीएस जिनका राम मंदिर के सीईओ लिए हुआ इंटरव्यू, अयोध्या से सीधे दिल्ली लौटे

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव अभियान चल रहा है। ट्रस्ट के लिए पहले पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तलाश जारी है। CEO पद के लिए कल से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। पहले दिन 8 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। पहले दिन कई IAS-IPS अफसर भी शामिल हुए।

सूत्रों का कहना है, सीईओ पद के लिए 5300 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। फिर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ओर से इन आवेदकों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हर उम्मीदवार से 40 से 50 मिनट तक बातचीत की गई।

कल मंगलवार को जिन लोगों

का इंटरव्यू लिया गया, उसमें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक पूर्व अफसर के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से 3 रिटायर अफसर भी शामिल थे। इनके अलावा जिन 4 अन्य लोगों का इंटरव्यू लिया गया उनका सेना से ताल्लुक थे। ये चारों पूर्व सैन्य अधिकारी हैं।

इंटरव्यू देने वालों में पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडेय के अलावा जौनपुर के जिलाधिकारी रहे दिनेश चंद्र भी शामिल थे, इनके अलावा पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा और समीर पांड्या भी इस रेस में शामिल हैं।

इंटरव्यू होते ही अयोध्या से दिल्ली रवाना

खास बात यह है कि इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर खासी गोपनीयता बरती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हर उम्मीदवार ने अयोध्या एयरपोर्ट पर अपने आने का कार्यक्रम ट्रस्ट को बता दिया था जिसके बाद उन्हें वहां से अलग-अलग गाड़ियों में अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया। चूंकि इंटरव्यू राम मंदिर में ही लिया जा रहा है और उम्मीदवारों को मीडिया से बात करने की मनाही है। ऐसे में इंटरव्यू देने के बाद, सभी प्रत्याशियों को प्लेन के जरिए नई दिल्ली भेज दिया गया। फिर दिल्ली से इन्हें अपनी-अपनी गंतव्यों के लिए उड़ान भरा।

कौन हैं ये IAS-IPS अफसर

राजेश पांडे भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर रहे हैं। प्रयागराज के रहने वाले पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल (IG) के पद से रिटायर हुए। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह लेखन क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। पिछले दिनों अंतहीन नाम से उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ है। यह उनकी दूसरी किताब है, इससे पहले वर्चस्व नाम से पहली किताब प्रकाशित हो चुकी है। आईएएस दिनेश चंद्र भी सीईओ पद के दावेदारों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले आईएएस दिनेश कई जिलों में जिलाधिकारी रहे हैं। वह कानपुर देहात, बहराइच, सहारनपुर और जौनपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। पूर्व आईएएस अफसर योगेश्वर राम मिश्रा भी में इस लिस्ट में शामिल हैं। योगेश्वर भी प्रयागराज से संबंध रखते हैं। रिटायर होने से पहले वह अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी जैसे जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा वह विंध्याचल डिविजन में कमिश्नर भी रहे। वह 30 मई 2024 को रिटायर हुए। इनके अलावा समीर पांड्या के बारे में कहा जा रहा है कि वह महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं।

नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा य एवं विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त परिसर एवं सामाजबके संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत युवा कनेक्ट के अंतर्गत "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम माननीय कुलपति प्रो. वंदना सिंह के संरक्षकत्व में आर्यभट्ट सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि यूथ आइकॉन शिवेंद्र प्रताप सिंह तथा नशा मुक्त वॉरियर श्री त्रिलोकीनाथ गुप्ता रहे। युवा अधिकारी श्री तन्मय मोहन ने स्वयंसेवकों को माई भारत के संबंध में जानकारी दी। इसके पश्चात माई भारत गीत एवं विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग पर आधारित चलचित्र प्रदर्शित किया गया।मुख्य अतिथि ने कहा कि "भारत की युवा शक्ति ही विकसित भारत की

सबसे बड़ी ताकत है। नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि नशे की लत युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मानसिक क्षमता, परिवार एवं सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है। युवाओं को नशे से दूर रहने, साथियों के दबाव का विरोध करने तथा नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपमानित करने के बजाय उपचार एवं परामर्श के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। संचालन अभिनव कीर्ति पांडेय, समन्वय डॉ. शशिकांत यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन नशा मुक्त परिसर एवं समाज के समन्वयक डॉ मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।

क्या ई-सिगरेट से भी हो सकता है लंग्स कैंसर, डॉक्टर ने बताया ये कितना खतरनाक

वैपिंग यानी ई-सिगरेट का क्रेज GenZ में ज्यादा देखा जाता है। जैसे नॉर्मल स्मोकिंग से कैंसर का खतरा रहता है क्या ई-सिगरेट भी हमें इसका शिकार बना सकती है।

नॉर्मल सिगरेट का धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। जैसे-जैसे सामान्य सिगरेट पीने वालों की संख्या कम हो रही है, वैसे-वैसे ई-सिगरेट (वेपिंग) का चलन तेजी से बढ़ा है। ई-सिगरेट को अक्सर सामान्य सिगरेट की तुलना में ज्यादा सेफ ऑप्शन और स्मोकिंग छोड़ने का प्रभावी तरीका बताकर प्रोमोट किया जाता है। लेकिन इन दावों के समर्थन में साइंटिफिक प्रूफ अभी भी पर्याप्त और मजबूत नहीं हैं। खासतौर से ई-सिगरेट के लंबे समय तक उपयोग से फेफड़ों पर होने वाले प्रभावों और फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को लेकर अभी भी व्यापक शोध जारी है

अब तक किए गए कुछ रिसर्च से संकेत मिलता है कि ई-सिगरेट का उपयोग फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। यह जोखिम उन लोगों में और अधिक हो सकता है जो ई-सिगरेट के साथ-साथ सामान्य सिगरेट का भी सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को "ड्यूल यूज़र" कहा जाता है।

एक्सपर्ट ने क्या कहा

डॉ। शिबा कल्याण बिस्वाल (हेड, पल्मोनोलॉजी, शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल) बताते हैं कि सिगरेट से निकलने वाले वाष्प (वेपर) में कई हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। इनमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो शरीर की कोशिकाओं और डीएनए (आनुवंशिक सामग्री) को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पशुओं पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि करीब एक साल तक ई-सिगरेट के वाष्प के कॉन्टेक्ट में रहने वाले चूहों में फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार विकसित हुआ।

इसके अलावा, ई-सिगरेट के तरल पदार्थों में यूज प्रोपिलीन ग्लाइकोल (Propylene Glycol) और बेंजोइक एसिड (Benzoic Acid) जैसे तत्व सेल्स में जलन, क्षति और फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं। शोध यह भी दर्शाते हैं कि पहले धूम्रपान कर चुके लोगों में ई-सिगरेट का उपयोग कैंसर के जोखिम को और बढ़ा सकता है। इसलिए फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए मरीज का वेपिंग इतिहास भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

फेफड़ों की बीमारी के मामले बढ़े

बीते कुछ सालों में वेपिंग से संबंधित गंभीर फेफड़ों की बीमारी के कई मामले भी सामने आए हैं, जिनमें मरीजों को सांस लेने में गंभीर तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेपिंग के जोखिम अप्रत्याशित हो सकते हैं, विशेषकर तब जब उत्पादों की गुणवत्ता का उचित नियमन न हो या उनमें अज्ञात रसायनों का उपयोग किया गया हो।

स्मोकिंग छोड़ने के लिए ई-सिगरेट पीना

धूम्रपान छोड़ने के लिए ई-सिगरेट अपनाने वाले कई लोग कहीं न कहीं नॉर्मल सिगरेट और ई-सिगरेट दोनों का सेवन करने लगते हैं। वो स्मोकिंग को छोड़ने के बजाय खुद को और बड़े खतरे में डाल देते हैं। इस वजह से उनकी निकोटीन पर निर्भरता बनी रहती है और वे अधिक हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं। ये सिचुएशन कई दशक पहले की उस गलत धारणा की याद दिलाती है, जब फिल्टर वाली सिगरेट को ज्यादा सेफ बताकर प्रचारित किया गया था, जबकि बाद में ये पाया गया कि वे भी उतनी ही हानिकारक थीं।

ड्रैगन फ्रूट के छिलके को फेंक देते हैं? जानिए इसके फायदे

ड्रैगन फ्रूट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? आमतौर पर लोग ड्रैगन फ्रूट का गूदा ही खाते हैं और उसके छिलकों को फेंक देते हैं। इस लेख में हम आपको ड्रैगन फ्रूट के छिलकों के कुछ अनसुने फायदों के बारे में बताएंगे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं।

त्वचा के लिए है फायदेमंद

ड्रैगन फ्रूट के छिलके में मौजूद फायदेमंद तत्व और विटामिन-सी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे बने फेस पैक या स्क्रब से त्वचा की चमक बढ़ सकती है और झुर्रियों से राहत मिल सकती है।

आप ड्रैगन फ्रूट के छिलकों को पीसकर पेस्ट बना सकते हैं और उसे चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी और निखरी हुई भी दिखेगी। नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत भी सुधर सकती है।

पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार

ड्रैगन फ्रूट के छिलके में फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। ये कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक होते हैं।

इसके अलावा फाइबर खाने का पाचन भी बेहतर बनाता है और आंत को स्वस्थ रखता है।

ड्रैगन फ्रूट के छिलके का सेवन करने से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और पेट की कई समस्याओं से बच सकते हैं।

दिल के लिए है फायदेमंद

ड्रैगन फ्रूट के छिलके में मौजूद पौष्टिक तत्व दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद फायदेमंद तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी सही बनाए रखते हैं।

इसके अलावा ये तत्व दिल की धमनियों को साफ रखते हुए रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। नियमित रूप से ड्रैगन फ्रूट के छिलके का सेवन करने से आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

वजन घटाने में सहायक

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ड्रैगन फ्रूट के छिलके आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट जल्दी भरता है और बार-बार खाने की इच्छा कम होती है।

इसके अलावा फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ड्रैगन फ्रूट के छिलके का सेवन करने से आप स्वस्थ तरीके से वजन घटा सकते हैं।

हड्डियों को मजबूत बनाने वाला

ड्रैगन फ्रूट के छिलके में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनसे हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है।

लाल लिपस्टिक का इतिहास जानकर हैरान रह जाएंगी आप, जानिए मेकअप में इसकी जगह

आजकल कई महिलाएं लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं। यह न केवल उन्हें आत्मविश्वास देती है, बल्कि उनके लुक में भी चार चांद लगा देती है। हालांकि, क्या आप जानती हैं कि लाल लिपस्टिक का इतिहास कितना पुराना और दिलचस्प है? प्राचीन मिस्र से लेकर आज के फैशन तक, लाल लिपस्टिक ने कई बदलाव देखे हैं। आइए जानते हैं कि लाल लिपस्टिक के पीछे की कहानी क्या है और यह कैसे एक फैशन आइकन बन गई।

प्राचीन मिस्र में था लाल लिपस्टिक का प्रचलन

प्राचीन मिस्र में लाल लिपस्टिक का उपयोग आम था। क्लियोपेट्रा जैसी राजकुमारियों ने इसे अपने चेहरे को सजाने के लिए इस्तेमाल किया था।

इस लाल रंग को बनाने के लिए वे कीटाणु, कीड़े और पौधों के हिस्सों का उपयोग करती थीं। यह रंग न केवल उनके चेहरे को सुंदर बनाता था, बल्कि इसे धूप और अन्य मौसम की मार से भी बचाए रखने में मदद करता था।

यह लाल रंग उनके सामाजिक स्थान को भी दर्शाता था।

मध्यकालीन यूरोप में था लाल लिपस्टिक का विरोध

मध्यकालीन यूरोप में लाल लिपस्टिक का उपयोग महिलाओं के लिए मुश्किल भरा था। धार्मिक नेताओं ने इसे शैतानी जादू मानकर इसका विरोध किया और इसे पहनने वालों को सजा देने तक की धमकी दी।

इसके बावजूद कई महिलाएं इसे अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थीं।

इस समय लाल लिपस्टिक को सामाजिक स्थिति और आकर्षण का प्रतीक माना जाता था, जिससे इसे पहनने वाली महिलाओं को सम्मान मिलता था।

विक्टोरियन युग में हुआ बदलाव

विक्टोरियन युग में लाल लिपस्टिक का उपयोग अधिक प्रचलित हो गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता था।

महिलाएं इसे छिपकर लगाती थीं, ताकि समाज की नजर न पड़े। इस समय तक लाल लिपस्टिक बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियां और मोम।

विक्टोरियन महिलाओं ने इसे आकर्षण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, भले ही उन्हें इसके लिए सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा हो।

20वीं सदी में बढ़ी लाल लिपस्टिक की प्रसिद्धि

20वीं सदी में लाल लिपस्टिक ने आधुनिक रूप धारण किया, जब अमेरिकी व्यवसायी एलिजाबेथ आर्डेन ने इसे बाजार में पेश किया।

उन्होंने इसे छोटे ट्यूब में पैक किया, ताकि महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद कई ब्रांड ने भी इस उत्पाद को अपने संग्रह में शामिल किया।

इस दौरान लाल लिपस्टिक ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और उन्हें स्वतंत्रता का अहसास कराने में अहम भूमिका निभाई।

आजकल लाल लिपस्टिक का उपयोग कैसे किया जाता है?

आजकल लाल लिपस्टिक कई प्रकारों में उपलब्ध है, जिसमें मैट, क्रीमी और ग्लॉसी फिनिश शामिल हैं। ये न केवल लंबे समय तक टिकती हैं, बल्कि त्वचा को पोषण देने वाले तत्व भी प्रदान करती हैं।

अब लाल लिपस्टिक केवल सौंदर्य उत्पाद नहीं, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है, जो हर महिला की मेकअप किट का अहम हिस्सा है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लाल लिपस्टिक का सफर कितना रोमांचक और

लकड़ी बनाम प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड इनमें से कौन-सा विकल्प है सब्जियां काटने के लिए बेहतर?

चॉपिंग बोर्ड एक जरूरी रसोई का सामान है, जिसका इस्तेमाल सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को काटने के लिए किया जाता है। बाजार में लकड़ी और प्लास्टिक के बने चॉपिंग बोर्ड, दोनों ही उपलब्ध हैं। हालांकि, इनमें से किसका चयन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है? इस लेख में हम लकड़ी और प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप सही चयन कर सकें।

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड के फायदे

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और सही देखभाल करने पर कई सालों तक काम करते रहते हैं।

इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्राकृतिक होते हैं और इनमें बैक्टीरिया को पनपने से रोकने की क्षमता होती है।

इसके अलावा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर काटने से खाने का स्वाद भी नहीं बदलता, जिससे खाना बनाते समय आपको कोई परेशानी नहीं होती।

ये प्लास्टिक के महीन कण भी नहीं छोड़ते हैं।

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड के नुकसान

लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्हें साबुन और गर्म पानी से धोने पर भी गंदगी पूरी तरह से हट नहीं पाती।

इसके अलावा लकड़ी के बोर्ड पर गहरी खरोंचें पडने से उनमें बैक्टीरिया फंस सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

इसलिए, इन्हें समय-समय पर सही तरीके से साफ करना जरूरी है और ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए इनकी देखभाल पर ध्यान दें।

प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड के फायदे

प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड हल्के होते हैं और इन्हें साफ करना भी आसान है। इन्हें साबुन और पानी से धोकर आसानी से साफ किया जा सकता है, जिससे इनमें किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया फंसने का खतरा कम रहता है।

इसके अलावा प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। इन सभी खासियतों के कारण प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना कई लोगों को पसंद है।

प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड के नुकसान

प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकना मुश्किल होता है और प्लास्टिक लंबे समय तक जमीन पर पड़ी रहती है।

इसके अलावा प्लास्टिक के बोर्ड पर तेज चाकू से काटने पर खरोंचें पड़ सकती हैं, जिनमें बैक्टीरिया फंस सकते हैं।

इन कारणों से प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड को लंबे समय तक इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें समय-समय पर बदलते रहना चाहिए।

किसका चुनाव रहेगा बेहतर?

अब सवाल यह है कि लकड़ी या प्लास्टिक में से किस चॉपिंग बोर्ड का चयन करना चाहिए? अगर आप लंबे समय तक टिकाऊ, प्राकृतिक और बैक्टीरिया मुक्त विकल्प चाहते हैं तो लकड़ी वाला चॉपिंग बोर्ड बेहतर रहेगा।

वहीं, अगर आप सफाई में आसानी चाहते हैं और सस्ते विकल्प की तलाश में हैं तो प्लास्टिक वाला चॉपिंग बोर्ड चुन सकते हैं।

दोनों ही विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपनी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार सही चयन करें।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, आईटी शेयरों में खरीदारी से मिला सपोर्ट

मुंबई, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को लगभग सपाट शुरुआत की। हालांकि बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में दबाव देखने को मिला, लेकिन आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में खरीदारी ने बाजार को संतुलित बनाए रखा।

कारोबार की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स 32.67 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 78,509.77 अंक पर खुला। वहीं एनएसई निफ्टी 50 8.70 अंक यानी 0.04 प्रतिशत फिसलकर 24,575.10 अंक पर कारोबार शुरू करता दिखाई दिया।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप में 0.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एवं टेलीकॉम इंडेक्स 0.73 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। इसके अलावा, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर्स में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला।

इसके विपरीत, बैंकिंग शेयरों में दबाव बना रहा। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.64 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.62 प्रतिशत तक गिर गया, जिससे बाजार पर कुछ दबाव बना रहा।

निफ्टी50 इंडेक्स में मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और एसबीआई लाइफ सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां रहीं।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें फिलहाल इक्विटी बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी संकेतक, जून तिमाही के उम्मीद से बेहतर कॉरपोरेट नतीजे और रुपए में स्थिरता बाजार को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की वापसी और बेहतर तिमाही नतीजे बाजार को मजबूती दे रहे हैं। उनका मानना है कि यदि विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है तो बाजार में हल्का सकारात्मक रुझान बना रह सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में मजबूत उपभोक्ता मांग वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कंपनियों की आय वृद्धि को समर्थन दे सकती है। साथ ही एफसीएनआर (बी) जमा योजनाओं में मजबूत प्रवाह रुपए को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना बढ़ेगी।

बाजार जानकारों का यह भी कहना है कि विदेशी निवेशक दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों से पूंजी निकालकर भारतीय बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह निवेश मुख्य रूप से टेलीकॉम, नवीकरणीय ऊर्जा, कैपिटल गुड्स और फार्मा सेक्टर में आ रहा है, जबकि अपेक्षाकृत आकर्षक वैल्यूएशन वाले बैंकिंग शेयरों में निवेश अभी भी सीमित बना हुआ है।

तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,400-24,450 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन माना जा रहा है। वहीं 24,750-24,800 का दायरा प्रमुख रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि निफ्टी सपोर्ट स्तरों के ऊपर बना रहता है तो बाजार में सकारात्मक रुझान जारी रह सकता है और गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर 24,800 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट आने पर तेजी और मजबूत हो सकती है।

वैश्विक बाजारों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.41 प्रतिशत बढ़कर 88.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.47 प्रतिशत बढ़कर 82.52 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करता रहा।

अमेरिकी बाजारों में सोमवार को हल्की कमजोरी देखने को मिली थी। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.06 प्रतिशत और नैस्डैक 0.32 प्रतिशत गिरावट के साथ बंद हुए थे।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेश प्रवाह, रुपये की चाल और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल घरेलू आर्थिक मजबूती और बेहतर कॉरपोरेट प्रदर्शन बाजार को सहारा देते नजर आ रहे हैं।

नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच खरीदे गए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर खरीद प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना मार्च 2028 तक बढ़ी, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलेगी 5,000 रुपए तक की सब्सिडी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ईवी-2डब्ल्यू) की खरीद पर प्रोत्साहन राशि जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और घरेलू ईवी विनिर्माण को मजबूत बनाना है।

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, विस्तारित पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए 11,900 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया गया है। योजना का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने और भारत को ईवी निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने पर रहेगा।

नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच खरीदे गए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर खरीद प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। सरकार ने यह प्रोत्साहन 2,500 रुपए प्रति किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) निर्धारित किया है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए प्रति वाहन होगी।

हालांकि, इस लाभ के लिए पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने योजना के तहत अधिकतम 45.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सहायता देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा 2,767 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि नई योजना में मिलने वाली सब्सिडी पहले की तुलना में कम है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच की दर से प्रोत्साहन दिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपए प्रति वाहन थी।

मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में ईवी की लागत में कमी को देखते हुए प्रति केडब्ल्यूएच प्रोत्साहन राशि की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।

इसके अलावा, सब्सिडी की राशि वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यानी अधिकतम निर्धारित प्रोत्साहन या वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत, दोनों में जो कम होगा, वही लाभ दिया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम ई-ड्राइव एक फंड-सीमित योजना के रूप में संचालित होगी। इसका मतलब है कि कुल भुगतान 11,900 करोड़ रुपए के निर्धारित बजट तक ही सीमित रहेगा। यदि योजना के लिए निर्धारित राशि या किसी विशेष घटक के लिए आवंटित फंड पहले ही समाप्त हो जाते हैं, तो उस घटक को बंद किया जा सकता है और उसके बाद नए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

योजना के तहत सभी श्रेणियों के लिए 31 मार्च 2028 अंतिम तारीख होगी, जबकि सब्सिडी दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2027 निर्धारित की गई है।

2029 तक बंद रहेगा होर्मुज! मुज्तबा की बिसात पर कैसे फंसे ट्रंप?

वॉशिंगटन, एजेंसी। समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत, फिर भी होर्मुज की संकरी नसें बंद पड़ी हैं। ईरान का अदृश्य चक्रव्यूह टूट नहीं रहा और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है, लेकिन अब ईरान होर्मुज में ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है, जो अमेरिका की लाचारी का जीवंत दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अमेरिका से युद्ध जीतने का फाइनल खांका खींच चुके हैं, जिसके केंद्र में होर्मुज को 2029 तक बंद करने की रणनीति छिपी है।

भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकाने और अपनी आगे की रणनितियों का क्लू देने की मंशा से करते आए हैं, लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है, वो है 'आपको पता चल जाएगा'। ट्रंप का ये रुख बताता है कि ईरान पर उनके तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है होर्मुज, जिसपर 2029 तक स्थायी ताला लग सकता है। इन कयासों और आशंकाओं की वजह इजरायल से आ रही रिपोर्ट्स हैं, जिसने अमेरिकी से लेकर पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है।

ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है वो ट्रंप के साथ किसी समझौता को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म होगा, तबतक ईरान सिर्फ प्रतीक्षा की स्थित में रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2029 तक होर्मुज स्ट्रेट इसी तरह बंद रहेगा। दरअसल ईरान का मानना है कि हालात उसके पक्ष में है और वो ट्रंप के साथ समझौता करने के बजाय उन्हें मात दे सकता है। ईरान ने अब तय कर लिया है कि ट्रंप को उसकी शर्तें मानकर या तो समझौता करना होगा या फिर उनके पूरे कार्यकाल में होर्मुज बंद रहेगा।

उधर, ईरान की इस बात पर पर्दा डालने के लिए ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि होर्मुज खुला है, ईरानी माइन्स हटा दी गई हैं। अब ट्रंप भले ही होर्मुज अपने नियंत्रण में होने और उसके खुलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक डेटा बता रहा है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सबसे निचले स्तर पर है। मैरीटाइम ट्रैफिक फर्म KPLER की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 5 दिन में होर्मुज से कुल 42 जहाज गुजरे हैं, जबकि युद्ध से पहले होर्मुज से 130 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें तेल टैंक, वाणिज्यिक जहाज से लेकर दूसरे छोटे-बडे.शिप शामिल थे।

ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहे ट्रंप

डेटा बताता है कि ट्रंप की कथनी और हकीकत में बड़ा फर्क है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ईरान के रुख पर है। आखिर वो किस आधार पर ट्रंप से 2029 तक तनाव जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल, दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के हर विकल्प की काट मुज्तबा के पास मौजूद है। ट्रंप के पास पहला विकल्प बड़े हमले करने का है, लेकिन ट्रंप इसे ज्यादा लंबे वक्त तक जारी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जबाव ईरान अरब देशों पर हमले करके देगा, जिनके बचाव के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर की कमी है। ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है- आर्थिक दबाव, जिसे वो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ईरान को तोड़ पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि आर्थिक दबाव ईरान सालों से झेल रहा है, पर अमेरिका उसे तोड़ नहीं पाया। वहीं, तीसरा विकल्प है- यथास्थिति बरकार रखना यानी जो जैसा है, वैसी ही चलने देना, लेकिन इन हालातों में होर्मुज कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरान का अप्रत्यक्ष नियंत्रण उसके ऊपर रहेगा और ट्रंप ईरानी शर्तें मानने के लिए विवश होंगे। यही वजह है कि ईरान 2029 तक ट्रंप से तनाव जारी रखने के लिए तैयार है, जो होर्मुज को ट्रंप के पूरे कार्यकाल के लिए बंद कर सकता है।

ईरान के पास ट्रंप के हर विकल्प की काट

इससे साफ है ट्रंप के हर विकल्प की काट ईरान के पास मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति विवश नजर आते हैं। अपनी और अमेरिका की साख बचाने के लिए उनपर होर्मुज को खोलने का दबाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नया युद्ध छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रंप की एक नई गलती साबित हो सकता है। NBC न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि होर्मुज पर नियंत्रण का कोई भी ऑपरेशन बेहद लंबा, खर्चीला और खूनी होगा, इससे अमेरिका और अरब देश बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में तेल संकट और बड़ा हो सकता है।

तेल संकट ऐसे होगा खत्म

अब तेल संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका युद्ध से पहले होर्मुज के वैकल्पिक मार्गों को विस्तार देने पर काम कर रहा है। UAE और सऊदी में नए ऑयल रूट पर पहले से काम जारी है। अब ऐसा ही वैकल्पिक मार्ग इराकी तेल के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जो सीरिया और तुर्किए से होकर जाता है। इराक 2 नई तेल पाइपलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। पहली पाइपलाइन इराक के बसरा से शुरू होकर तुर्किए के रास्ते भूमध्य सागर तक जाएगी। ये पाइपलाइन बसरा से पहले हदीथा तक पहुंचेगी और हदीथा में इराक का मुख्य पंपिंग स्टेशन है। हदीथा से पाइपलाइन उत्तर की ओर बढ़ेगी और सलाहुद्दीन प्रांत के बैजी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाएगी।

यहां इसे किर्कुक से फिशखाबूर तक जाने वाली पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। फिशखाबूर में पाइपलाइन तुर्किए के सीहान पोर्ट जाने वाली इराक-तुर्किए पाइपलाइन से जुड़ेगी। ये पाइपलाइन करीब 1200 से 1300 किमी में फैली होगी। इसकी तेल सप्लाई क्षमता 22.15 लाख बैरल प्रति दिन रहने का अनुमान है। क्षमता बढ़ाने के लिए इराक बैजी से फिशखाबूर तक सीधी पाइपालाइन की भी मरम्मत कर रहा है, जो सालों से बंद पड़ी है।

अमेरिका में अब कागजी इमिग्रेशन खत्म? भारतीयों के ग्रीन कार्ड से सिटिजनशिप तक क्या बदलेगा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को कागजी प्रक्रिया से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) अब ग्रीन कार्ड, सिटिजनशिप, शरण, वर्क परमिट और फैमिली पिटीशन जैसे कई इमिग्रेशन आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था धीरे-धीरे अनिवार्य करेगा। हालांकि, 12 अगस्त 2026 से हर आवेदन तुरंत ऑनलाइन नहीं होगा। किसी खास फॉर्म पर ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य करने से पहले USCIS को 60 दिन का नोटिस देना होगा। नया नियम उन फॉर्म पर लागू किया जा सकता है, जो कम से कम 180 दिनों से ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।

इस बदलाव के दायरे में ग्रीन कार्ड आवेदन और रिन्यूअल, फैमिली पिटिशन, सिटिजनशिप यानी नेचुरलाइजेशन, शरण, वर्क परमिट और टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेट (TPS) जैसे आवेदन आ सकते हैं। नियम लागू होने के बाद ज्यादातर आवेदकों को USCIS ऑनलाइन अकाउंट के जरिए आवेदन करना होगा। जहां सुविधा उपलब्ध होगी, वहां भरा हुआ PDF और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकेंगे। लेकिन हर फॉर्म पर यह नियम अलग-अलग समय पर लागू होगा और 60 दिन का नोटिस मिलेगा।

USCIS का कहना है कि कागजी आवेदन में मैनुअल डेटा एंट्री, स्कैनिंग, स्टोरेज, शिपिंग और फाइल संभालने में काफी समय और पैसा लगता है। ऑनलाइन फाइलिंग से गलतियां कम करने, प्रोसेसिंग तेज करने और फर्जीवाड़े की पहचान आसान होने की उम्मीद है। 2025 के वित्त वर्ष में USCIS ने 1.4 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्रोसेस की थीं। उसके पेपर लॉकबॉक्स सिस्टम ने करीब 45.3 करोड़ पन्नों की सबमिशन संभालीं। इस व्यवस्था पर करीब 39.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जबकि डाक पर ही 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ।

जिन लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं है, वे छूट मांग सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को ई-फाइलिंग से परेशानी होती है, तो USCIS उसके मामले को अलग से देखेगा। इसके लिए अलग प्रक्रिया और शुल्क रखा गया है। कुछ मामलों में फीस में छूट की सुविधा भी होगी।

भारतीयों के लिए क्यों अहम?

भारतीय नागरिक अमेरिका में रोजगार के आधार पर मिलने वाले ग्रीन कार्ड की लंबी कतार में सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में हैं। बड़ी संख्या में भारतीय H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के जरिए ग्रीन कार्ड और नागरिकता के लिए भी कई भारतीय आवेदन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन से ग्रीन कार्ड की कतार खत्म नहीं होगी। अगस्त 2026 के वीजा बुलेटिन में भारत के लिए EB-2 की अंतिम मंजूरी की तारीख उपलब्ध नहीं थी, जबकि EB-3 के लिए 1 जनवरी 2014 की तारीख थी। वहीं, दोनों श्रेणियों में आवेदन जमा करने की तारीख 15 जनवरी 2015 थी। यानी आवेदन जमा करने और ग्रीन कार्ड मिलने की तारीख अलग-अलग होती है।

किसे फायदा, किसे परेशानी?

जो भारतीय पहले से ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल दस्तावेज और इमिग्रेशन वकीलों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बदलाव आसान हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग माता-पिता, कम डिजिटल जानकारी वाले लोग और कमजोर इंटरनेट वाले इलाकों के आवेदकों को परेशानी हो सकती है। उन्हें अकाउंट बनाने, दस्तावेज स्कैन करने और PDF अपलोड करने में मदद की जरूरत पड़ सकती है।

क्या ग्रीन कार्ड जल्दी मिलेगा?

सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग से ग्रीन कार्ड जल्दी नहीं मिलेगा। डिजिटल व्यवस्था आवेदन लेने और कुछ प्रोसेसिंग चरणों को तेज कर सकती है, लेकिन ग्रीन कार्ड की मंजूरी प्रॉयोरिटी डेट, वीजा नंबर और संबंधित कैटेगरी में उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारत के EB-2 में FY2026 की उपलब्ध संख्या मई 2026 तक इस्तेमाल हो चुकी थी। नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा।

भारतीय आवेदक अभी क्या करें?

अभी सभी फॉर्म के लिए कोई एक अंतिम तारीख तय नहीं हुई है। जिस फॉर्म पर ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य होगी, USCIS पहले 60 दिन का नोटिस देगा। इसलिए आवेदकों को USCIS के अपडेट देखते रहना चाहिए और पासपोर्ट, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, रोजगार से जुड़े कागज और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखनी चाहिए। यानी बदलाव आवेदन करने के तरीके में है, ग्रीन कार्ड की कतार में नहीं। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन फाइलिंग से कागजी काम आसान हो सकता है, लेकिन ग्रीन कार्ड और सिटिजनशिप की कतार खत्म नहीं होगी।

एसआईआर के 33 लाख विवाद को सुलझाने के लिए बंगाल में सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल, हर दिन 300 फैसले...अब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाने के बाद अब इन फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में दाखिल अपीलों की सुनवाई भी सवालों के घेरे में है। मामला सिर्फ नाम कटने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों में मामलों की सुनवाई की रफ्तार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने में दाखिल की गई अपीलों पर SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल के कामकाज पर नजर रखेगा, लेकिन वह ट्रिब्यूनल के फैसलों के लिए कोई

डेडलाइन तय नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से यह बताने को कहा है कि अब तक कितनी अपीलों का निपटारा हुआ है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी। मोहना की बेंच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए कई निर्देश देने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट मे क्यों कहा था ऐसे अपीलों के निपटारे में लग जाएगा 30 साल का वक्त

SIR प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए। इन लोगों को अपने नाम दोबारा शामिल कराने के लिए अपील का रास्ता दिया गया। इन अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इनकी अध्यक्षता पूर्व हाईकोर्ट जज कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। लंबित अपीलों की संख्या करीब 33-34 लाख बताई जा रही है। जुलाई में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक करीब 33 लाख अपीलों में से लगभग 30 हजार का ही निपटारा हुआ था, यानी कुल मामलों का एक फीसदी से भी कम। यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई में टिप्पणी की थी कि अगर अपीलों के निपटारे की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो लंबित मामलों को निपटाने में करीब 21 साल लग सकते हैं।

फिर 30 साल का गणित कहां से आया?

मान लीजिए करीब 33 लाख अपीलें लंबित हैं। ट्रिब्यूनल रोजाना औसतन 300 मामलों का निपटारा करता है। ऐसे में अगर इस स्पीड से अपीलों को निपटारा किया जाए तो 11,000 दिन लगेंगे। 11,000 दिन को 365 से भाग देने पर करीब 30।1 साल आ रहा है। यानी अगर 33 लाख मामलों का बैकलॉग हो और रोजाना सिर्फ 300 मामलों का ही निपटारा हो, जबकि इस दौरान नए मामले न जुड़ें और काम की रफ्तार बिल्कुल न बढ़े, तो पूरा बैकलॉग खत्म करने में करीब 30 साल लगेगा। हालांकि यह महज एक गणितीय अनुमान है,कलकत्ता हाईकोर्ट का 21 साल वाला अनुमान भी उस समय की वास्तविक निपटान दर के आधार पर था।

19 ट्रिब्यूनल हैं, फिर भी इतनी धीमी रफ्तार क्यों?

सवाल यही है कि जब पश्चिम बंगाल में 33 लाख अपीलों को निपटान के लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं तो लाखों अपीलों का निपटारा तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में इसी सवाल पर फोकस किया। कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना है कि ट्रिब्यूनल कितने मामलों का निपटारा कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं और उनकी वास्तविक डिस्पोजल रेट क्या है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसका पूरा डेटा मांगा है। अदालत के सामने यह मुद्दा भी आया कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ट्रिब्यूनल तक पहुंचना आसान नहीं है। ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने और जजों की संख्या आबादी के के हिसाब से नहीं है। इसका साफ मतलब है अपीलों का डिस्पोजल रेट में ट्रिब्यूनल की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम करने की क्षमता और पूरी प्रक्रिया की पहुंच भी शामिल है।

क्या वोटर लिस्ट से बाहर होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है?

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट से बाहर हुए और जिनकी अपीलें लंबित हैं, उन्हें राशन जैसे लाभ मिलने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि PDS या दूसरे कल्याणकारी लाभों का मुद्दा अलग कानूनी मामला है और इसके लिए हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रिब्यूनल को यह आदेश नहीं दिया कि हर अपील इतने दिनों में निपटाई जाए। CJI ने चुनाव आयोग से पूछा है कि कि अब तक कितनी अपीलें निपटाए गई हैं कोर्ट 25 अगस्त को फिर इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ अपील करने का अधिकार मिल जाना पर्याप्त नहीं है।

'राष्ट्रगान गाना हमेशा गर्व का पल रहा', श्रेया घोषाल ने 'जन गण मन' को दी अपनी आवाज; शेयर की खास पोस्ट

मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल की आवाज में 'जन गण मन' का खास वर्जन हाल ही में रिलीज हुआ है। इस खास प्रस्तुति को लेकर श्रेया ने अपने अनुभव और भावनाएं शेयर की हैं। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने करियर में कई सुपर हिट गाने दिए हैं। अब उन्होंने हाल ही में उन्होंने राष्ट्रगान 'जन गण मन' को अपनी आवाज दी है, जिसके बाद उन्होंने अपने अनुभव को भी शेयर किया।

आईएएनएस से बातचीत में श्रेया घोषाल ने कहा कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसे ऐसे गीत को अपनी आवाज देने का मौका मिले, जो पूरे देश को एक भावना और पहचान के साथ जोड़ता है।उन्होंने कहा, 'एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसे ऐसे गीत को अपनी आवाज देने का मौका मिले, जो पूरे देश को एक भावना और एक पहचान के साथ जोड़ता है? मुझे खुशी है कि मेरी यह प्रस्तुति अब सभी लोगों के लिए जारी की जा रही है।'

श्रेया ने आगे कहा कि वह चाहती हैं कि लोग उनके इस वर्जन को अपने-अपने तरीके से महसूस करें और राष्ट्रगान के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करें।

श्रेया घोषाल ने सोशल मीडिया पर भी 'जन गण मन' के इस खास वर्जन को शेयर किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान का क्षण है। पेश है 'जन गण मन' का मेरा वर्जन।'

20 से ज्यादा भाषाओं में गा चुकी हैं 3,000 से ज्यादा गाने

श्रेया घोषाल भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक हैं।

उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी समेत 20 से ज्यादा भाषाओं में 3,000 से ज्यादा गाने गाए हैं।

उन्होंने साल 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' से प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी।

इस फिल्म में उनके गाए 'बैरी पिया', 'सिलसिला ये चाहत का', 'डोला रे डोला', 'मोरे पिया' और 'काहे छेड़ मोहे' जैसे गाने काफी पसंद किए गए थे।

'देवदास' के गानों ने श्रेया को रातोंरात पहचान दिला दी थी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अपनी शानदार आवाज और गायकी के लिए श्रेया को कई बड़े और प्रतिष्ठित अवॉर्ड भी मिल चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है।

भारत में 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे

डेस्टिन डैनियल क्रेटन की सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी है। यह भारत के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। यह उपलब्धि फिल्म ने देश में 30 जुलाई को रिलीज होने के बाद सिर्फ 11 दिनों में हासिल की है। स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करके देश की सबसे बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बन गई है। टॉम हॉलैंड की मुख्य भूमिका वाली इस सुपरहीरो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड लगातार तोड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये, तीन दिनों में 200 करोड़ रुपये और आठ दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।

अब, दूसरे वीकेंड में लगभग 100 करोड़ रुपये की और कमाई के साथ स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे ने पूरे भारत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। यह भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है।

स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे ने जेम्स कैमरून की 2022 की साइंस-फिक्शन फिल्म अवतारः द वे ऑफ वॉटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमबीडी रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवतारः द वे ऑफ वॉटर ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 483 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था।

इसके बाद मार्वल की एक और फिल्म, रूसो ब्रदर्स की एवेंजसःर् एंडगेम (2019) आती है, जिसने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 438 करोड़ रुपये की कमाई की और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। इससे पहले आई रूसो ब्रदर्स की फिल्म एवेंजसःर् इन्फिनिटी वॉर (2018) चौथे नंबर पर है। इसने 291 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। इस तरह अब तक सिर्फ तीन हॉलीवुड फिल्में ही भारत के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में स्पाइडर-मैनः ब्रांड न्यू डे ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसकी कमाई 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है, जो अब 1।67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें से अकेले विदेशों से 1 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है, जबकि अमेरिकी बाजार से 655 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है।

इस रफ्तार से लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक चलेगी, चाहे भारत हो या विदेश। यह 2 बिलियन डॉलर की कमाई का आंकड़ा छू सकती है। भारत में यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में हिट रही है।

सलमान खान– संजय दत्त की अंतरराष्ट्रीय फिल्म 7 डॉग्स की भारत में रिलीज तारीख का ऐलान

सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि की तौयारी में बिजी हैं। उनकी इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सलमाल खान ने अपनी इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म 7 डॉग्स के बारे में एक बड़ी जानकारी शेयर की है। इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में रिलीज होने के बाद, फिल्म अब भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

सलमान खान ने ऐलान किया है कि उनकी इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स आखिरकार 21 अगस्त को इंडिया के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म का टीजर शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, सबसे बड़े मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है! इस घोषणा में बताया गया कि 7 डॉग्स अरब दुनिया की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली हिट फिल्म है और ये भी कन्फर्म किया गया कि इंडियन ऑडियंस आखिरकार इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को बड़े पर्दे पर देख पाएंगी।

बता दें, फिल्म का निर्देशन बिलाल फलाह और आदिल एल अरबी ने किया है। ये फिल्म इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में रिलीज हो चुकी है, जिसमें सलमान खान और संजय दत्त की छोटी लेकिन खास झलक देखने को मिली थी। अब इंडिया में फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी खुश हैं।

पिछले साल फिल्म का टीजर सामने आने के बाद सलमान खान और संजय दत्त के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। टीजर के पहले ही मिनट में संजय दत्त की झलक दिखाई गई थी, जिसमें वो किसी पर बंदूक ताने नजर आए। उनके चेहरे पर खतरनाक अंदाज देखने को मिला। वहीं टीजर के दूसरे हिस्से में सलमान खान की एंट्री हुई।

फिल्म की कहानी इंटरपोल ऑफिसर खालिद अल-अज्जाजी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट 7 डॉग्स के बड़े सदस्य घाली अबू दाऊद को पकड़ लेता है। फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त कैमियो रोल में नजर आएंगे, जबकि करीम अब्देल अजीज और अहमद एज्ज लीड रोल में हैं। फिल्म को सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख ने प्रोड्यूस किया है। सलमान खान और संजय दत्त फरवरी 2025 में तीन दिनों की शूटिंग के लिए रियाद भी गए थे।

सलमान खान और संजय दत्त के फैंस दोनों को एक बार फिर साथ पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इससे पहले दोनों साजन, चल मेरे भाई और ये है जलवा जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा दर्शकों को पसंद आई है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti।com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail।com